राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 19 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं।

-महाभारत

ट्रंप की नूराकुश्ती

मध्य-पूर्व में अमेरिका और इस्राइल को नया शिकार मिल गया है। ट्रंप और नेतनयाहू की जुगलबंदी से ईरान तबाही की ओर बढ़ रहा है। अलग-थलग पड़ चुका ईरान कितना प्रतिरोध कर पाएगा यह तो भविष्य ही बताएगा क्योंकि जहां से मदद की उसे उम्मीद थी वह रूस तीन साल से यूक्रेन से पार नहीं पा सका है, और चीन इस्राइल को संयम रखने वाली नसीहतें देकर काम चला रहा है। इस समय दुनिया की जो हालत है उसमें सबने अपने-अपने टारगेट तय किए हुए हैं, चीन को भी कालांतर में ताइवान से निपटना है। ट्रंप की चेतावनियों से तो लगता है कि अमेरिका युद्ध में कूद ही पड़ा है। अमेरिका पहले अपने शत्रु तैयार करता है और फिर विध्वंसक रासायनिक, परमाणु हथियार बनाने और लोकतंत्र हनन के अनर्गल आरोप लगा कर लड़ाई करता है। इराक,

अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया की तबाही इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। दरअसल, अमेरिका की मजबूत हथियार लॉबी, जो नये-नये हथियार ईजाद करती है, के हथियारों का कहीं परीक्षण भी तो होना चाहिए। युद्ध के बहाने हथियारों का परीक्षण हो जाता है और कई देश दहशत में भी आ जाते हैं। हथियारों की बिक्री का यह उसका आजमाया हुआ तरीका है। इस्राइल की मदद के बहाने अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा है जो ईरान उसके साथ पांच दौर की परमाणु वार्ता कर चुका था, छठे दौर की वार्ता से ठीक पहले अमेरिका ने इस्राइल को उकसा कर हमला करवा दिया। ईरान परमाणु हथियार विकसित करने का सपना छोड़ कर परमाणु के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहमत होने ही वाला था कि इस्राइल ने युद्ध छेड़ दिया। इस खेल में ट्रंप की मिलीभगत है। ट्रंप अब ईरानियों को तेहरान छोड़ जाने की चेतावनी दे रहे हैं। वह अब खेल को लोकतंत्र स्थापना के नाम पर खेलना चाहते हैं। ईरान के शीर्ष नेता खामेनेई को उन्होंने विलेन घोषित कर दिया है और ईरानी जनता को खामेनेई से मुक्ति दिलाने के बहाने भड़काने की पूरी तैयारी है। इसी के चलते ट्रंप यह जानने का दावा भी कर रहे हैं कि खामेनेई कहां छिपे हैं। यह युद्ध अब पूरी तरह प्रोपेगैंडा के आधार पर लड़ा जा रहा है। इसमें पश्चिमपरस्त मीडिया की अहम भागीदारी है। इस्राइल और अमेरिका के दावों को तो बढ़ा-चढ़ा कर बताया-दिखाया जा रहा है। ईरान में हुए नुकसान को ही मिर्च मसाला लगा कर बताया जा रहा है जबकि ईरान का प्रतिरोध और इस्राइल में हो रही क्षति की बातें कम करके बताई जा रही हैं। ट्रंप मामले में खालिश नूराकुश्ती कर रहे हैं, और विश्वसनीय नहीं रहे।

गंभीर मसला है ये

अहमदाबाद-लंदन एयर इंडिया विमान हादसे के बाद अब तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की 66 उड़ान रद्द हो चुकी हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है परंतु सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने, फ्लाइट ऑपरेशन सुव्यवस्थित करने व समय पर उड़ान भरने जैसे निर्देश दिए गए हैं। हालांकि एक दिन में सात अंतरराष्ट्रीय उड़ान रद्द करने का मसला सामान्य नहीं कहा जा सकता। तकनीकी खामी के नाम पर उड़ान रद्द करने से व्यवस्था व रखरखाव को लेकर संदेह गहराता है। इस बीच, ओमान से वाया कोच्चि से दिल्ली आ रही उड़ान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में बम होने की सूचना के बाद यह निर्णय लेना पड़ा। महानिदेशालय के नियमों, आईएएआई की मांगों व 2019 की इंसपेक्शन रिपोर्ट के बावजूद देश के कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे विमानों को बनाने वाली दो

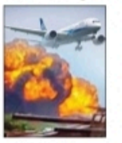

कंपनियां-अमेरिकी बोइंग और यूरोप की एयरबस-ही प्रमुख हैं। बोइंग कई सालों से बुरी स्थिति झेल रही है। उसके विमान न सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, बल्कि उनमें तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर भी विशेषज्ञ हैरान हैं। आरोप तो ये भी हैं कि कंपनी ने मुनाफे और शेयरों की कीमतें बढ़ाने को तवज्जो देने में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की। अधिक बचत के लिए कटौतियां और छंटनियां होती रहीं जिससे समस्याएं गंभीर होती चली गईं और विमान दुर्घटनाएं बढ़ गईं। मगर कंपनी ने इन पर ध्यान देने की बजाय पायलटों के मत्थे दोष मंढना चालू कर दिया। इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि विमान हादसे के बाद अचानक तकनीकी खामियों की खबरें, हो सकता है अति सतर्कता का नतीजा हों जिनके प्रति पूर्व में लापरवाही बरती जा रही थी। मगर यदि बोइंग में दिक्कतें हैं तो इन पर कड़ाई किया जाना जरूरी है। विशेषज्ञ पहले भी बोइंग व एयरबस को मिलने वाली चुनौतियों की चर्चा करते रहे हैं। चीन व ब्राजील की कंपनियां इन्हें टक्कर देने वाली साबित हो सकती हैं। तकनीक, सॉफ्टवेयर या निर्माण को लेकर की जा रही सांठ-गांठ का खमियाजा यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है। किसी भी तरह की लीपा-पोती को बर्दाश्त करने की बजाय जरूरी है कि संबंधित मंत्रालय और प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

कटाक्ष/ सहीराम

फिर मौका है

लो जी, एक बार फिर मौका आ गया वॉर रुकवाने का। यह मौका अमेरिका को तो जी गाहे-बगाहे मिल ही जाता है। आखिर तो वह अमेरिका है। और अमेरिका का राष्ट्रपति अगर ट्रंप हो तो फिर वह मौका न भी मिले तो छीन लेता है। जैसे इधर हमारा पाकिस्तान से जो नन्हा सा युद्ध हुआ, उसे रोकने का श्रेय उसने न हमें लेने दिया और न ही पाकिस्तान को। बोला-इसका श्रेय तो मैं ही लूंगा। तुम नहीं लेने दोगे तो मैं जबर्दस्ती लूंगा। शोर मचा दूंगा। हल्ला काट दूंगा। क्या कर लोगे। आखिर तो मैं अमेरिका ही नहीं, ट्रंप भी तो हूं। कुछ लोग इसे करेला और नीम चढ़ा भी कह सकते हैं। तो अमेरिका को तो यह मौका मिलता ही रहता है। क्योंकि न तो वह दुनिया में युद्ध रुकने देता है और न ही चौधराहट छोड़ता है। कोई उसे विश्व दरोगा कहता है, कोई उसे दुनिया का चौधरी कहता है। पता नहीं आखिर वह बला क्या है। लेकिन अब तो यह मौका एक फिर से हमें भी मिल रहा है। एक बार पहले जब रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने का मौका मिला था तो वह यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों के बहाने से मिला था। पता नहीं किसकी नजर लगी कि वह श्रेय हमें मिल नहीं पाया। फिर अभी हम ट्रंप भी तो नहीं हुए कि श्रेय जबर्दस्ती ले लें। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है यह नजर मणिपुर की ही लगी हो। अब उन्हें कौन बताए कि जिस मणिपुर को खुद ही किसी की नजर लगी हो, वह किसी और को क्या नजर लगाएगा भला। फिर भी जलकुकड़े कहने से बाज नहीं आए कि मणिपुर की मार-काट तो रुकवा नहीं पा रहे। उसके बाद तो खैर हमारा अपना ही पाकिस्तान से युद्ध हो गया। वॉर रुकवाने से वॉर करने तक का सफर यूं रहा।

अब इसे मेहरबानी तो किस की कहें, पर एक बार फिर वॉर रुकवाने का मौका मिल रहा है। खैर बहाना एक बार फिर से छात्र ही बन रहे हैं। अब ईरान में भी हमारे छात्र फंसे हुए हैं। जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा कर-जैसा कहा गया-उन छात्रों को निकाला गया था, वैसे ही अब इन छात्रों को भी निकाल ही लेना चाहिए। फिर जैसे पुतिन और जेलेंस्की से दोस्ती थी, वैसी ही दोस्ती बीबी-यानी नेतन्याहू और ईरानी नेताओं-से भी है ही। एक से थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होगी तो दूसरों से थोड़ी हल्की होगी। दुनिया घूमने का आखिर, इतना फायदा तो होना ही चाहिए। नहीं क्या?

दम तोड़ रहा है माओवाद

सामयिक

प्रवीण कुमार

माओवाद, जिसे भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी विचारधारा रही है जिसने कई दशकों तक देश के भीतर युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखी। इसकी शुरुआत 1967 में प. बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी जब चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने भूमि सुधारों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई के नाम पर सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। लेकिन समय के साथ यह आंदोलन सामाजिक न्याय की मांगों से भटक कर हिंसा, अपहरण, हत्या और विध्वंस की राह पर बढ़ गया। लंबे समय तक यह आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रहा परंतु अब यह सवाल प्रासंगिक हो गया है कि क्या माओवाद अब अपने अंतिम चरण में तो नहीं पहुंच गया है?

एक समय था जब माओवादी प्रभाव देश के 90 से अधिक जिलों में फैला था। यह क्षेत्र, जिसे 'लाल गलियारा' कहा जाता था, देश के अंदरूनी हिस्सों में फैले घने जंगलों और पहाड़ियों में स्थित था। मसलन, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के इलाके। इन क्षेत्रों में राज्य की उपस्थिति कमजोर थी और माओवादियों ने खुद को एक वैकल्पिक सत्ता के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने ग्राम न्यायालय चलाए, 'जन अदालतों' में सजा दी, ठेकेदारों से वसूली की और युवाओं की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण दिया। लेकिन पिछले एक दशक में हालात तेजी से बदले हैं। अब न माओवादी पहले जैसी ताकत रखते हैं, न ही उनके विचार में वह आकर्षण रह गया है जो कभी हाशिए पर पड़े लोगों को जोड़ता था। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त रणनीति ने माओवाद को कमजोर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सबसे पहले, सुरक्षा बलों की तैनाती और उन्हें आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया। 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' जैसी योजनाओं के माध्यम से माओवादियों के गढ़ में सीधे प्रवेश किया गया। अनेक माओवादी शिविर नष्ट किए गए और सैकड़ों उग्रवादी मारे गए या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 'बस्तर फाइटर्स' नामक विशेष बल का गठन कर स्थानीय युवाओं को शामिल किया गया जिससे क्षेत्र में न सिर्फ सुरक्षा बलों की स्वीकार्यता बढ़ी, बल्कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में कई माओवादी नेताओं ने हथियार डाल दिए। झारखंड में 'नक्सल मुक्त झारखंड' अभियान के तहत पलामू, लातेहार, चतरा जैसे प्रभावित जिलों में निरंतर अभियान चला कर माओवादी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 2023 में अकेले लातेहर

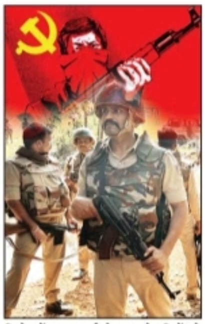

जिले में 27 हार्डकोर माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया जो राज्य सरकार की रणनीति की सफलता दर्शाता है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में कमांडो कार्रवाइयों से माओवादियों को भारी नुकसान हुआ।

दूसरा अहम पहलू विकास रहा। सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों को विकास योजनाओं से जोड़ कर जनता का विश्वास जीतने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। ओडिशा के मलकानगिरि, कोरापुट जैसे दुर्गम जिलों में सड़क, बिजली और मोबाइल टॉवर जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया गया जिससे न सिर्फ ग्रामीणों का संपर्क बाहरी दुनिया से बढ़ा, बल्कि माओवादियों की गतिविधियों पर भी लगाम लगी। आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड्स बल की सक्रियता ने विशाखापत्तनम और अल्लूरी सीताराम राजू जिलों में माओवादी प्रभाव को कम है। वहीं 'आकांक्षी जिलों' की सूची में शामिल सुकमा, गढ़चिरौली, सिंहभूम, मलकानगिरी जैसे जिलों में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया जिससे सुरक्षा बलों की पहुंच तो आसान हुई ही, ग्रामीणों के जीवन में भी परिवर्तन आया। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिली और वे माओवाद की बजाय नये जीवन की ओर उन्मुख हुए।

माओवादी आंदोलन का कमजोर होना सिर्फ सैन्य कार्रवाई या योजनाओं तक सीमित नहीं रहा। वैचारिक स्तर पर भी यह आंदोलन खोखला हो चुका है। नई पीढ़ी, जो अब स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में जी रही है, को बंदूक की राजनीति में कोई भविष्य नहीं दिखता। वे अवसर चाहते हैं, सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण युवाओं ने भी अब इस हिंसात्मक रास्ते से दूरी बना ली है। आदिवासी समुदाय, जिनके नाम पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, अस्पताल तक पहुंचना चाहता है और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी चाहता है। हालिया वर्षों के आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। 2010 में माओवादी हिंसा के 2,200 से अधिक मामले सामने आए थे, वहीं 2023 में यह संख्या घट कर लगभग 500 रह गई। इसी तरह माओवादी प्रभाव वाले जिलों की संख्या 96 से घट कर मात्र 45 तक आ गई है। इनमें भी कुछ गिने-चुने जिले जैसे बीजापुर, सुकमा और गढ़चिरौली ही शेष हैं, जहां कभी-कभार छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं। संकेत साफ हैं कि माओवादी आंदोलन अपना चरम पार कर चुका है, और अब अवसान की ओर बढ़ रहा है।

हालांकि चुनौतियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं। माओवादी अब शहरी नेटवर्क के माध्यम से अपनी विचारधारा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों और मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से माओवाद को वैचारिक समर्थन देने के आरोप भी कई बार चर्चा में आए हैं। इसके अलावा, कुछ दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में प्रशासनिक सुस्ती, भ्रष्टाचार और गरीबों की उपेक्षा अब भी माओवादियों को भावनात्मक समर्थन पाने का अवसर देती हैं। कई क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को अब भी उनके जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसका फायदा माओवादी उठाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की धीमी रफ्तार इन क्षेत्रों में असंतोष को जन्म देती है। लेकिन अब माओवादियों के प्रयास न तो पूरी तरह संगठित हैं, न ही प्रभावशाली। ये बस कमजोर दीये की तरह हैं, जो बुझने से पहले कुछ क्षणों के लिए तेज लौ के साथ टिमटिमाता है। इसलिए जब सवाल पूछा जा रहा कि क्या माओवाद अंतिम सांसें गिन रहा है, तो इसका जवाब 'हां' है।

(लेख में विचार निजी हैं)

माओवादी आंदोलन वैचारिक स्तर पर खोखला हो चुका है। नई पीढ़ी, जो अब स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में जी रही है, को बंदूक की राजनीति में कोई भविष्य नहीं दिखता। वे सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। यही वजह है कि ग्रामीण युवाओं ने भी अब इस माओवादी हिंसात्मक रास्ते से दूरी बना ली है। आदिवासी समुदाय, जिनके नाम पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब लोकतंत्र में अपनी भागीदारी चाहता है

धान का रकबा बढ़ा

- देश में मौजूदा वर्ष के खरीफ मौसम में धान का रकबा बढ़ा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों में बताया गया है कि 13 जून तक देश में धान का रकबा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4 लाख हेक्टेयर से 0.53 प्रतिशत बढ़ कर 4.53 लाख हेक्टेयर हो गया है
- आंकड़ों के मुताबिक, दलहन का रकबा 2.60 लाख हेक्टेयर से 3.07 लाख हेक्टेयर हो गया है। श्रीअन्न का रकबा मामूली घट कर 5.90 लाख हेक्टेयर से 5.89 लाख हेक्टेयर रह गया है
- तिलहन की बुआई 1.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ कर 2.05 लाख हेक्टेयर जबकि गन्ना का रकबा 54.88 लाख हेक्टेयर से बढ़ कर 55.07 लाख हेक्टेयर हो गया है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम को अपनी विदेश यात्रा से लौटते में अमेरिका आमंत्रित किया लेकिन मोदी ने व्यवस्ताओं के नाम पर असमर्थता जतला दी। अंदाजा लगाइए व्हाइट हाउस में लंच पर ट्रंप किसके मेजवान? वही पाकिस्तान के स्वघोषित फील्ड मार्शल। नई दिल्ली खुश, इस्लामाबाद खुश, लेकिन 'सौदेबाज' ट्रंप बेचारगी में। आखिर, पहलगाम घटना के बाद आतंक के प्रायोजक के मेजबान पर कौन यकीन करेगा।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

डिजिटल होगी जाति जनगणना

मुद्दा **प्रमोद भार्गव**

दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई है। कोविड महामारी के कारण 2021 में होने वाली यह जनगणना अब शुरू होगी। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जातिवार जनगणना कराने की मांग कर रहा था। अचानक मोदी सरकार ने जातिवार जनगणना कराने का फैसला लेकर उसे चौंका दिया क्योंकि अब यह मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सभी वर्गों की प्रमुख जातियों के साथ उपजातियों की जनगणना के आंकड़े जब सामने आएंगे, तब यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सैद्धांतिक रूप से जातिगत गणना कराना उचित था या नहीं?

ई-बाजार, ई-आवेदन, ई-रेल व बस में आरक्षण ई-भुगतान के बाद अब ई-जनगणना यानी डिजिटल गिनती होगी। इस गिनती में जाति की गिनती भी साथ-साथ होगी। इसमें जन्म और मृत्यु, दोनों ही डिजिटल जनगणना से जुड़े होंगे। हर जन्म के बाद डिजिटल जनगणना खुद ही अद्यतन हो जाएगी और जब किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम खुद ही डाटा से डिलीट हो जाएगा। सेंसर रजिस्टर यानी जनगणना में बच्चे के जन्म, माता-पिता, जाति और जन्म स्थान की जानकारी समेत 16 भाषाओं में 36 प्रश्नों के उत्तर दर्ज हो जाएंगे। बालक जब 18 साल का होगा तो खुद ही उसका नाम चुनाव आयोग के पास चला जाएगा। नतीजतन, उसका मतदाता पहचान पत्र बनने के साथ मतदाता सूची में भी नाम स्वयमेव दर्ज हो जाएगा। फिर जब किसी की मौत हो जाएगी तो ऑनलाइन जनगणना के डाटा से उस शख्स का नाम खुद ही डिलीट भी हो जाएगा। इस तरह से जनगणना का डाटा हमेशा खुद अद्यतन होता रहेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर करीब 12000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डिजिटल जनगणना की घोषणा 1 फरवरी, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। जनगणना-2021 में नागरिकों को गणना में शामिल होने की एक बेहतर और अनूठी ऑनलाइन सुविधा दी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का अधिकार देने के लिए नियमों में परिवर्तन किए हैं। जनगणना (संशोधन), 2022 के अनुसार परंपरागत तरीके से तो जनगणना घर-घर जाकर सरकारी कर्मचारी करेंगे ही, लेकिन अब नागरिक स्व-गणना के माध्यम से भी अनुसूची प्रारूप भर सकता है। इसके लिए

पूर्व नियमों में 'इलेक्ट्रॉनिक फार्म' शब्द जोड़ा गया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा दो की उपधारा (एक) के खंड आर में दिया गया है। इसके अंतर्गत मीडिया, मैग्नेटिक, कंप्यूटरजनित माइक्रोचिप या इसी तरह के अन्य उपकरण में तैयार कर भेजी या संग्रहित की गई जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दी गई जानकारी माना जाएगा यानी एनरायड मोबाइल से भी अपनी गिनती दर्ज की जा सकेगी, जो आजकल घर-घर में उपलब्ध है। इस ऑनलाइन प्रविष्टि के अलावा घर-घर जाकर भी जनगणना की जाएगी। गिनती के विकेंद्रीकरण के इस नवाचार से देश जहां 10 साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा वहीं देश के पास प्रति माह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक आंकड़े मिलते रहेंगे।

जनगणना में निरंतरता इसलिए भी जरूरी है कि देश-दुनिया में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग सात सौ करोड़ हो चुकी है। धरती पर जितनी तेजी से मानव समुदायों की आबादी उन्नसवीं सदी में बढ़ी है, उतनी तेजी से बढ़ोतरी पहले कभी दर्ज नहीं हुई। एक अनुमान के मुताबिक ईसवी सन एक में धरती पर कुल आबादी लगभग तीस करोड़ थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत में दुनिया की जनसंख्या एक अरब के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। इन शताब्दियों में जन्म दर की मात्रा अधिक होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर बेहद मंदी थी। प्रकृति पर निर्भर गर्भनिरोधकों से दूर और उपचार की आसान-सुलभ पद्धतियों से अनजान स्त्री-पुरुष बच्चे तो खूब पैदा करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मर जाया करते थे। बीमारियों की पहचान-उपचार से नियंत्रण के चलते बीसवीं शताब्दी के पहले ही तीन दशकों में आबादी दोगुनी होकर करीब पौने दो अरब के आंकड़े को छू गई थी।

हरेक दस साल में की जाने वाली जनता-जनार्दन की गिनती में करीब 34 लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख ग्रामों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल होता है। यह काम तब और बोझिल हो जाता है, जब किसी कर्मचारी-दल को उसके स्थनीय दैनंदिन कार्य से दूर कर उसे दूरांचल गांव में भेज दिया जाता है। ऐसे हालात में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर जाते हैं। इन विस्थापितों का जनगणना के समय स्थायी ठिकाना कहां है, जनगणना करने आए दल को यह पता लगाना मुशकिल होता है?

प्रकृति-वश **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

संसार में जो अधिक पढ़ा-लिखा हो या जिसे लौकिक व्यवहार का अधिक अनुभव हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग में इतना ही पर्याप्त नहीं है। सांसारिक ज्ञान से ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा-सर्वदा भावनाओं, वृत्तियों और प्रकृति के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहता है क्योंकि जब तक शरीर, मन, इंद्रियों और संसार के संपर्क में वह रहता है, तब तक प्रकृति के गुणों का प्रभाव उस पर पड़ता है। एक लौकिक ज्ञानी, चाहे जितना ही स्थिर और संयमित क्यों न दिखाई दे, के भीतर जो सूक्ष्म अहंकार हैं, वे कभी-कभी जाग्रत होकर उसे ऐसे आचरण की ओर ले जा सकते हैं, जो उसकी सामान्य ज्ञान-दृष्टि से विपरीत हो। ज्ञानी का ज्ञान होना और उस ज्ञान को जीवन में उतारना-ये दोनों अलग अवस्थाएं हैं। ज्ञान एक उपलब्धि है, परंतु उसमें निरंतर स्थित रहना तपस्या है। हां, इतना अवश्य है कि जब हम कहते हैं कि कोई ज्ञानी प्रकृति के वश हो गया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वह सदा अज्ञानता में डूब गया। इसका अर्थ है कि उस क्षण में उसकी अंतरात्मा पर प्रकृति के गुणों-रज, तम या सत-का प्रभाव अधिक हुआ और उसने उसी प्रभाव के अनुरूप कर्म कर लिया। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि ज्ञानी के ऐसे कर्म क्षणिक होते हैं, और उसके भीतर स्थित विवेक शीघ्र ही उसे उस आचरण की असंगतता का भान करा देता है। इसीलिए ज्ञानी आत्म-निरीक्षण में सक्षम होता है, अपने आचरण की समीक्षा करके आवश्यक सुधार कर सकता है। अज्ञानी जहां अपने कर्मों को लेकर जड़ हो जाता है, वहीं ज्ञानी अपने ही आचरण का निरीक्षण करके स्वयं को परिवर्तित कर सकता है। इसलिए महंत स्वामी महाराज समझाते हैं कि जीवन की यह सच्चाई हमें स्वीकार करनी चाहिए कि लौकिक ज्ञान या किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता। जब तक मन और इंद्रियां हैं, जब तक अहंकार का सूक्ष्म रूप शेष है, तब तक प्रकृति का प्रभाव कभी भी किसी भी क्षण में प्रकट हो सकता है। यह ज्ञान की असफलता नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरी है। यही कारण है कि बड़े-बड़े संत और योगी भी निरंतर साधना में लीन रहते हैं।

रीडर्स मेल

नशे का फैलता जाल

देश में नशे का जाल फैलता जा रहा है। यह एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है। नशे के कारोबार में अत्यधिक लाभ होने की वजह से आसानी से इसे संरक्षण प्राप्त हो जाता है, इसी वजह से समाज के संपन्न एवं धनी वर्ग धड़ल्ले से नशे का सेवन कर रहे हैं। बॉलीवुड कलाकारों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यह वर्ग नशे की गिरफ्त में डूबा हुआ है। कई बार बॉलीवुड कलाकारों के ऊपर भी प्रतिबंधित नशीली पदार्थों के सेवन के आरोप लग चुके हैं, लेकिन रईसजादे और नामचीन हस्तियों को कानून का डर नहीं रहता। युवा वर्ग नशे की चपेट में आता जा रहा है। युवाओं को नशे के जाल से बचाना समाज और सरकार का कर्त्तव्य है।

हिमांशु शेखर, गयाजी

युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए

आज शांति कहीं पर भी नहीं है। जिधर देखो, उधर तबाही के मंजर नजर आते हैं। पिछले तीन वर्षों से रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है, इस्राइल-फिलिस्तीन भी काफी समय से आमने-सामने लड़ ही रहे थे कि अब इस्राइल, ईरान में भी युद्ध छिड़ गया है। भारत को पाकिस्तान शांति से रहने नहीं दे रहा है। आए दिन खुराफात करके तनातनी का माहौल पैदा करता रहता है। हम कैसी दुनिया में सांस ले रहे हैं, जहां मौत और अशांति के सिवा कुछ भी नहीं है। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो, गौतम बुद्ध ने शांति, महात्मा गांधी के अहिंसा की शिक्षा-दीक्षा के संदेश दिए लेकिन ये सब बीते दिनों की बात हो गई है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। लेकिन यहां सभी को युद्ध की पड़ी है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से खलबली मचाता रहता है। पाकिस्तान अपनी करगुजारियों से बाज नहीं आ रहा है। आखिरकार, यह मातमपुर्सी वाले दिन कब पीछा छोड़ेंगे? कहीं कोई ओर-छोर दिखाई नहीं दे रहा है। शांति-अहिंसा के साथ जियो और जीने दो की नीति पर चलते हुए सभी देश मानव जिंदगी का आनंद क्यों नहीं लेते हैं? आखिर, क्यों कीड़े-मकोड़े की तरह मरने-मारने पर उतारू हैं?

हेमा हरि उपाध्याय, 'क्षअत', उज्जैन

जातिगत संकीर्णता से उबरना होगा

कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब जातिगत संकीर्णता को त्याग कर समस्त प्राणी जगत के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। केवल वर्ग विशेष के लिए काम करने वाले को कदापि महान नहीं कहा जा सकता। राम, कृष्ण से लेकर पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, विवेकानंद, दयानंद आदि ने अपना जीवन अपनी जातियों के लिए नहीं अपितु संपूर्ण समाज और देश के लिए समर्पित किया था। किंतु आज हमने इन सभी महापुरुषों को अपनी-अपनी सुविधानुसार जातियों के खांचों में ढाल लिया है। आज हर राजनैतिक दल का नेता अपने हर संबोधन में 'बाबा साहेब भीमराव का संविधान' कहना नहीं भूलता क्योंकि यह वाक्यांश देश के 17% मतदाताओं तक सहज ही पार्टी का संदेश देने में सफल हो जाता है। न तो इन नेताओं को बाबा साहेब से कोई सहानुभूति है, और न ही संविधान के प्रति निष्ठा है। यही हाल ऐतिहासिक योद्धाओं को लेकर भी है।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक [illegible] द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, [illegible], 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। | स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* |
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 301
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR/GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु [illegible]

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 105

जी-7 बैठक पर गतिरोध हावी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में नियम-व्यवस्था आधारित लोकतंत्र और व्यापार पर पश्चिमी देशों के बीच आपसी सहमति की बुनियाद दरकने का एक और उदाहरण जी-7 देशों की बैठक में दिखा। कनाडा के प्रांत अल्बर्टा के कनानास्किस में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मेजबानी में आयोजित जी-7 देशों की 51वीं बैठक में यह बिखराव साफ नजर आया। दो दिनों तक चली इस बैठक के कार्यक्रमों और जिन विषयों पर चर्चा होनी थी उनमें वृद्धि एवं साझा आर्थिक संपन्नता के लिए आवश्यक रकम पर आपसी साझेदारी मजबूत करना, वृद्धि के लिए एआई से जुड़ी पहल एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना और प्रवासियों की अवैध घुसपैठ आदि शामिल थे। इसके साथ ही ईरान और यूक्रेन संकट पर भी चर्चा होनी थी। मगर इन विषयों पर कोई संयुक्त बयान जारी नहीं होने से जी-7 देशों के बीच आपसी मतभेद उजागर हो गए। हालांकि, अलग-अलग विषयों पर कुछ संयुक्त बयान जरूर आए। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के साए में हुई इस बैठक के पहले ही दिन ट्रंप बैठक बीच में छोड़कर वाशिंगटन लौट गए। ट्रंप के इस निर्णय से जी-7 शिखर सम्मेलन गतिरोध का शिकार हो गया।

ईरान व इजरायल के बीच जारी घमासान के दौरान इस बैठक में 'गाजा में संघर्ष विराम सहित पश्चिम एशिया में तनाव कम करने' पर एक संक्षिप्त बयान अवश्य आया मगर इसमें ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम का जिक्र नहीं था। अमेरिका की आपत्ति के बाद यूक्रेन के समर्थन में संयुक्त बयान भी हटा दिया गया। हालांकि, ट्रंप की आपत्ति के बाद जी-7 की 51वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे कनाडा की तरफ से जारी सार वक्तव्य में एक छोटा हिस्सा शामिल किया गया जिसमें 'आर्थिक प्रतिबंध सहित रूस पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए सभी विकल्प तलाशने' की बात कही गई। ट्रंप इस बैठक में अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार सौदा करना चाहते थे मगर कनाडा, जापान और यूरोपीय संघ किसी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला।

कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से सम्मेलन में कुछ जान आई और कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। बैठक में भारत-कनाडा द्विपक्षीय रिश्तों में आई खटास कम हुई। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे लेकिन जी-7 सम्मेलन के दौरान मोदी और कार्नी की बैठक के द्विपक्षीय ताल्लुकात सुधरने की पहली संभावना नजर आई। इस दिशा में 'सोच-विचार कर उठाए गए पहले कदम' के रूप में दोनों नेता अपने-अपने उच्चायोग दोबारा भेजने पर सहमत हो गए। दोनों प्रधानमंत्री व्यापार, दोनों देशों के बीच संबंध एवं संपर्क से जुड़े कई क्षेत्रों में वरिष्ठ एवं कार्य-स्तरीय ढांचा एवं चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए। आने वाले समय में और भी कूटनीतिक कदम उठाए जाने की संभावना है। दोनों नेताओं की बैठक पर कनाडा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 'पार-देशीय अपराध एवं दमन, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था' पर भी चर्चा हुई।

भारत और कनाडा के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं इसलिए निश्चित रूप ये सही सकारात्मक संकेत हैं। कनाडा की कुल आबादी में 5 प्रतिशत हिस्सा भारतीय मूल के लोगों की है। किंतु, कुछ प्रमुख प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। सबसे पहले, ओटावा के इस आरोप का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि कनाडा की धरती पर एक सिख पृथकतावादी नेता की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ रहा है। साल 2023 में दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने की यह सबसे बड़ी वजह थी। कनाडा में ताकतवर सिख कनाडा गुट कार्नी पर दबाव बना सकते हैं। मोदी को आमंत्रित करने के कार्नी के निर्णय के खिलाफ सिख प्रदर्शनकारियों ने कैलगरी में एक विरोध रैली का आयोजन किया। कैलगरी जी-7 के आयोजन स्थल से सबसे नजदीक शहर है। इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई 35 मिनट की बातचीत से कुछ प्रगति हुई है। इस साल नई दिल्ली में 'क्वाड' के अगले शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी का निमंत्रण राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में 'क्वाड' पर कोई खास प्रगति नहीं हुई थी इसलिए इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। मगर ट्रंप के नेतृत्व में 'क्वाड समूह कितनी प्रगति करेगा यह फिलहाल एक अनुत्तरित प्रश्न है।

ऐपल से बढ़ी चीन की धमक भारत के लिए अहम सबक

इकलौती ऐपल ने ही चीन को विनिर्माण का गढ़ बना दिया। अब भारत को भी विविधता की लहर पर सवार होकर वही करना चाहिए।

बता रहे हैं आकाश प्रकाश

मैं इन दिनों एक बेहतरीन किताब पढ़ रहा हूं- 'ऐपल इन चाइना - द कैप्चर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंपनी।' किताब फाइनैंशियल टाइम्स के पत्रकार पैट्रिक मैकगी ने लिखी है, जो सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और ऐपल पर खबरें करते हैं। किताब में दो दिलचस्प बातें हैं। पहली, 1996 में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी ऐपल कैसे महज 15 सालों में दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई। दूसरी, कैसे ऐपल ने चीन को तीसरी दुनिया के कम कौशल वाले विनिर्माण केंद्र से दुनिया के सबसे बड़े और बेहतरीन विनिर्माण केंद्र में बदल दिया। ऐपल कंपनी जब बनी थी तो उत्पादन खुद ही करना चाहती थी। मगर लागत के बोझ और दूसरी कंपनियों के साथ होड़ की वजह से उसने ठेके पर काम कराना शुरू कर दिया।

पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे ऐपल पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों में आखिरी थी, जो ठेके पर विनिर्माण कराती थी। शुरू में उसने ठेका कोरिया की एलजी को दिया, जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में फैली थी। किताब बताती है कि कैसे फॉक्सकॉन और टेरी गौ आए और कैसे ताइवान से शुरू होकर समूचा विनिर्माण चीन में ही होने लगा। लेखक बताते हैं कि चीन को विनिर्माण में अग्रणी बनाने और वहां कुशल तथा बेहतर आपूर्ति श्रृंखला बनाने में ऐपल ने कितनी अहम भूमिका निभाई।

आईफोन दुनिया में आज तक आए उत्पादों में शायद सबसे अनूठा और कामयाब है। 2007 में 50 लाख आईफोन बिके थे मगर 2015 में आंकड़ा 23 करोड़ तक पहुंच गया। अभी तक कुल 3 ट्रिलियन डॉलर के आईफोन बेचे जा चुके हैं। दुनिया के स्मार्टफोन बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 20 फीसदी है मगर बाजार के कुल मुनाफे का 80 फीसदी इसी के पास आता है। अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उलट इसके दाम केवल बढ़े हैं। पहला आईफोन 499 डॉलर का था और आज इसकी कीमत 1,000 डॉलर से अधिक है।

लेखक ने विभिन्न साक्षात्कारों में कहा है कि ऐपल अपने आपूर्तिकर्ताओं के जरिये चीन में करीब 30 लाख लोगों को रोजगार देता है। ऐपल ने वहां करीब 2.8 करोड़ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। इधर भारत में समूचा आईटी सेवा उद्योग केवल 60 लाख लोगों को रोजगार देता है।

2015 तक ऐपल चीन में सालाना 55 अरब डॉलर लगा रही थी और 2018 तक उसने वहां 18 अरब डॉलर मूल्य की विशेष मशीनरी भी लगाई। गुणवत्ता से मोह के कारण उसने विनिर्माण तकनीक और गुणवत्ता मानक के प्रशिक्षण पर भी भारी धनराशि खर्च की। किताब बताती है कि आपूर्तिकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए ऐपल ने कैसे हजारों इंजीनियर भेजे और कुछ को तो वहीं तैनात कर दिया।

अब हमें महसूस हुआ कि चीन विनिर्माण में इतना आगे इसलिए है क्योंकि उसके आपूर्तिकर्ताओं को ऐपल से प्रशिक्षण मिला। ऐपल अपने आकार (उत्पादन के चरम पर चीन 250 अरब डॉलर से अधिक कीमत के 50 करोड़ आई-गैजेट बना रहा था), गुणवत्ता और फिनिश पर ध्यान तथा आपूर्ति श्रृंखला को सहारा देकर प्रशिक्षित करने की इच्छा के कारण अनूठी कंपनी थी। आपूर्ति भले ही ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन कर रही थी मगर उत्पाद और कल-पुर्जे चीन में ही तैयार हो रहे थे। अब चीन की आपूर्ति श्रृंखला दुनिया में सबसे किफायती और बेहतरीन है। किसी अन्य देश के पास इतने बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण आईफोन तैयार करने की क्षमता नहीं है।

मैकगी कहते हैं कि इस विनिर्माण कौशल ने ही ड्रोन तथा इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में चीन का दबदबा कायम करा दिया। चीन के स्मार्टफोन उद्योग यानी हुआवे, शाओमी, ओपो और वीवो की विश्व बाजार में 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। इसकी जड़ें भी उसी आपूर्ति श्रृंखला में तलाश की जा सकती हैं। पुस्तक यह भी बताती है कि ऐपल के सामने कैसी चुनौतियां हैं। उसे विविधता लाने की जरूरत है क्योंकि उसके सामने भूराजनीतिक चुनौतियां हैं। लेकिन वह चीन को नाराज नहीं कर सकता है, जबकि निर्यात पर नियंत्रण और वीजा प्रतिबंध के जरिये चीन विविधता लाने ही नहीं दे रहा।

भारत के लिए यह चौंकाने वाली बात है कि कैसे एक विश्वस्तरीय बहुराष्ट्रीय संस्थान श्रेष्ठ विनिर्माण का पूरा माहौल तैयार कर देता है। अन्य वैश्विक दिग्गज भी आपूर्ति श्रृंखला पर ऐसा ही असर डाल सकते हैं। स्मार्टफोन निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की नीति अच्छी है। जैसे-जैसे ऐपल का पैमाना बढ़ेगा, लागत और कम होगी। हमें कंपनियों का भारत में स्वागत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। किताब भी बताती है कि चीन में ऐपल को कैसे मदद मिली थी। उसे रियायती जमीन से किफायती श्रम तक सब दिया गया। हमें समझना चाहिए कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में दाखिल होने का शानदार मौका हमारे पास है। आर्थिक नजरिये से ऐपल के पास चीन से बाहर जाने की कोई वजह नहीं है। गुणवत्ता या लागत के मामले में उसके लिए चीन की जगह कोई नहीं ले सकता।

यह बदलाव भू-राजनीति की वजह से आ रहा है। नई आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना आसान नहीं होगा। ऐपल ऐसा करेगी क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। भारत इसका स्वाभाविक ठिकाना है मगर हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारी तकदीर कितनी अच्छी है और देश के लिए यह कितना अच्छा होगा। हमें यह भी समझना होगा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पहुंचे बगैर हम विश्वस्तरीय विनिर्माता नहीं बन सकते।

हमें विभिन्न क्षेत्रों की ऐसी अग्रणी कंपनियां तलाशनी होंगी, जो खुद बहुत कम उत्पादन करती हों, जैसे अपैरल और फुटवियर में नाइकी या स्पेशियलिटी केमिकल्स में सिंजेंटा। इनमें से कई कंपनियां खुद बहुत कम उत्पादन करती हैं और चीन से बहुत अधिक उत्पादन कराती हैं। उन पर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के दबाव के बीच भारत पीएलआई के जरिये खुद को विकल्प बनाकर पेश कर सकता है। ऐपल ने दिखा ही दिया है कि एक बड़ी कंपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला की सूरत बदल सकती है।

ऐपल उपकरणों की अंतिम चरण की असेंबलिंग का कुछ काम भारत में करने लगी है। उसके कलपुर्जे भी यहां बनने लगे तो बड़ी कामयाबी होगी। इसमें भी पीएलआई मददगार हो सकती है। भारत में उत्पादन ले जाने के हर प्रयास का चीन विरोध करेगा। इसलिए इस काम में कई साल लग सकते हैं और हमें अधीरता से बचना होगा।

मुनाफे पर नजर वाले कुछ भारतीय समूह ऐपल के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाने के इच्छुक होंगे। हमें चीन से सीखना चाहिए। ऐपल को आपूर्ति से ज्यादा पैसा बेशक न मिले मगर हमें वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने का कौशल और क्षमता मिल जाएंगे।

चीन ने ऐपल की सफलता का फायदा उठाकर उन्नत विनिर्माण तंत्र बना लिया। केवल एक कंपनी की बदौलत वह दुनिया में उच्चस्तरीय निर्माण का केंद्र बन गया। हमें भी उसी तरह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता की लहर का पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि हम अपनी विनिर्माण और आपूति श्रृंखला व्यवस्था कायम कर सकें। हमारे पास एक विशिष्ट अवसर है और हमें सरकार के हर स्तर पर हर नीतिगत कदम उठाना चाहिए ताकि यह संभव हो सके। हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

(लेखक अमांसा कैपिटल से जुड़े हैं)

देश में असंख्य दुर्घटनाओं के खिलाफ जंग बहुत जरूरी

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

पिछले दिनों अहमदाबाद में विमान दुर्घटना, ग्रेटर मुंबई में लोकल ट्रेन दुर्घटना और बेंगलूरु के क्रिकेट स्टेडियम में भगदड़ के हादसे हुए। कुछ ही दिनों में तीन दुखद घटनाएं! और इनसे पहले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन महाकुंभ और स्टेडियम में भगदड़ भीड़ के उन्माद का उदाहरण है और भगदड़ की सदियों पुरानी कहानी में नए अध्याय हैं।

ग्रेटर मुंबई के मुंब्रा और दीवा स्टेशनों के बीच हुई दुखद दुर्घटना में सबसे कम जान गई। उसमें चार यात्रियों की मौत हुई और नौ घायल हुए जबकि अन्य घटनाओं में मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मगर लोकल ट्रेन की दुर्घटना बहुत भारी समस्या की हल्की सी झलकी भर है और हताहतों की संख्या कम होने के बाद भी इस पर सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए।

मुंबई उपनगरीय रेल यानी लोकल ट्रेन प्रणाली में हर साल 2,500 से 3,000 असमय मौतें होती हैं। यह औसतन 7 मौत रोजाना है, जिनमें ज्यादातर ट्रेन से गिरने या पटरी पार करते समय ट्रेन से टकराने के कारण होती हैं। इनमें से कुछ खुदकुशी भी हो सकती हैं, जिन्हें हादसों की श्रेणी में रख दिया जाता है। मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली में 2022 में आधिकारिक तौर पर खुदकुशी के 76 मामले दर्ज हुए। इसके बरअक्स लंदन की रेल प्रणाली में होने वाली दुर्घटनाओं में हर साल औसतन तीन लोग मरते हैं, और 40 खुदकुशी करते हैं। पेरिस में हर साल खुदकुशी समेत लगभग 60 मौतें होती हैं।

मुंब्रा-दीवा हादसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन के दरवाजे से लटके कुछ यात्री बगल की पटरी पर जा रही दूसरी ट्रेन से बाहर लटके यात्रियों से टकरा गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े 2022 के बाद से उपलब्ध नहीं हैं। 2022 में सभी ट्रेन हादसों में 21,000 से अधिक मौतें दर्ज की गईं और इनमें से 73 फीसदी लोगों के ट्रेन से गिरने या बगल की ट्रेन की चपेट में आने के कारण हुई थीं। इनमें 10 फीसदी से ज्यादा मौतें केवल मुंबई में हुईं।

इस हादसे के बाद लोकल ट्रेन के डिब्बों में खुद बंद होने वाले दरवाजे लगाने का आश्वासन दिया गया। इससे मौतों की संख्या तो कम हो जाएगी मगर लोगों में आक्रोश भी बढ़ेगा। लोग डिब्बों से बाहर इसलिए लटकते हैं क्योंकि उन्हें समय पर अपने काम पर पहुंचना होता है। क्षमता से ज्यादा काम कर रही रेल प्रणाली में अत्यधिक भीड़ और गहमागहमी वाले समय पर अधिक ट्रेन चलाना मुश्किल है। किंतु मुंबई को यात्रियों के परिवहन के तरीके खोजने होंगे चाहे मेट्रो हो या बस हों या रेल क्षमता बढ़ाई जाए। सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ाने और ऑटो-डोर शुरू करने के अलावा रेलवे के बुनियादी ढांचे को कुशलता के साथ सुधारना होगा, जैसे अधिक फुटब्रिज बनाना और यात्रियों को पटरी पार करने या ट्रेन से कूदने या उतरने का जोखिम नहीं उठाने के लिए जागरूक किया जाए। यह मुश्किल काम है मगर होना तो चाहिए। यह हर महानगर की समस्या है और अन्य शहर इसे बेहतर तरीके से संभालते हैं।

दिल्ली में भी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में काफी मौतें होती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो शुरू होने के बाद इसमें कमी आई है और डीटीसी बसों पर गति काबू में रखने वाले गवर्नर लगाए गए हैं। कोलकाता में ऐसी मौतें मुंबई या दिल्ली की तुलना में बहुत कम होती हैं। शायद इसलिए कि कोलकाता के यात्री समय की पाबंदी को तवज्जो नहीं देते। देश की वित्तीय राजधानी को चलाने वाले अधिकारियों के लिए शर्म की बात है कि उपनगरों के साथ फैलती मुंबई कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के बिना काम नहीं कर सकती और दिन में सात लोगों की जान लेने वाली प्रणाली कुशल नहीं कही जा सकती। ये मौतें अलग-अलग और कम संख्या में होती हैं, इसलिए इनसे ज्यादा आक्रोश भी नहीं होता। भारतीय रेलवे को राजनीतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, न ही नगर निगम के अधिकारियों को, जिन्हें रेलवे के साथ मिलकर परिवहन बुनियादी ढांचा फिर तैयार करना चाहिए और सुरक्षा के लिए क्षमता बढ़ानी चाहिए।

इधर भगदड़ परंपरा से जुड़ी हुई है। भारत में धार्मिक जोश के कारण भगदड़ होना नई बात नहीं है। अंग्रेजों के समय में 1800 के दशक में पुरी रथयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में मौत हुई थीं। भीड़ को संभालना निश्चित रूप से किसी भी प्रशासन के कौशल का हिस्सा होना चाहिए। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि किसी त्योहार या विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ कहां इकट्ठा होगी। सरकारें विरोध प्रदर्शनों के पैमाने को कम करने के लिए कई तरीके अपनाती हैं, बसों के मार्ग बदल देती हैं, स्टेशनों को बंद कर देती हैं, ड्रोन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस दल तैनात करती हैं और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए घेराबंदी करती हैं। इसी तरह के तरीके खुश भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किए ही जाने चाहिए।

आपका पक्ष

दिल दहलाने वाली त्रासदी: विमान हादसों से सबक जरूरी

अहमदाबाद में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा केवल एक तकनीकी खामी नहीं, बल्कि पूरे विमानन तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब देश में हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हवाई यात्रा आम नागरिकों के लिए भी सहज हो रही है, ऐसे में इस तरह की त्रासदियां लोगों के भरोसे को गहरा आघात पहुंचा सकती हैं। भारत इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत देश के छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। बीते दशक में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 159 हो चुकी है। हवाई यात्रा अब केवल अमीरों की सुविधा नहीं, बल्कि आम लोगों की जरूरत बन चुकी है। अप्रैल 2025 में घरेलू हवाई यात्रा में भी 10.2 फीसदी की वृद्धि हुई और पिछले साल 17 नवंबर को एक ही दिन में 5 लाख यात्रियों का सफर इस बात का प्रमाण है कि भारत में हवाई यात्रा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसे में किसी एक बड़ी दुर्घटना से आम लोगों का भरोसा टूटना देश के विमानन क्षेत्र की प्रगति पर प्रश्नचिह्न खड़े कर सकता है। वर्तमान में भारत में अधिकांश विमान सेवाओं का संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इन कंपनियों का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जन है, लेकिन क्या वे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। सुविधाओं में कुछ हद तक कटौती सहनीय हो सकती है, पर सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विमान निर्माता कंपनी बोइंग की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। क्या तकनीकी खामी पहले से ज्ञात थी। क्या उसकी समय पर मरम्मत हुई। इन प्रश्नों के उत्तर जरूरी हैं।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

पिछले सप्ताह दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के अंतिम संस्कार में शामिल उनके पिता

ग्राहकों को मिलेगा सस्ता कर्ज

सीआरआर कम होने से बैंकों के पास जहां ग्राहकों को ऋण देने के लिए अधिक धन रहता है, वहीं रीपो दर घटने से बैंकों को केंद्रीय बैंक से अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर पैसा मिलता है। वाणिज्यिक बैंक इन लाभों को अपने ग्राहकों को हस्तांतरित कर देते हैं जिससे उन्हें कार, होम या निजी ऋण कम ब्याज दर मिल जाता है। ब्याज पर हुई बचत और आसानी से मिले ऋण से उपभोक्ता खर्च और निवेश बढ़ता है और विकास को गति मिलती है। हालांकि रीपो दर कम होने से बैंक में जमा कराने वाले ग्राहकों को थोड़ा नुकसान होता है। मुद्रास्फीति के उतार चढ़ावों को काबू में रखने और अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करने में रीपो दर और सीआरआर कारगर उपकरण हैं।

ईश्वर चंद गर्ग, कैथल, हरियाणा

आर्थिक विकास के लिए सही

आर्थिक प्रगति बनाए रखने के लिए आरबीआई द्वारा रीपो दर और सीआरआर में कटौती करना अर्थव्यवस्था की सराहनीय पहल है। बैंकों द्वारा कम ब्याज दरों पर मकान ,वाहन, शिक्षा, उपभोक्ता व अन्य ऋण मिल जाने से बाजार में बिक्री और उद्योगों में उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। आर्थिक मंदी और धीमी विकास दर के दौर में रीपो दर कम करना एक अत्यंत प्रभावी उपाय है।

आदित्य नामदेव, ईमेल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अर्णाला को बुधवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। अर्णाला उथले जल के युद्धपोत श्रृंखला का पहला जहाज है और यह पानी की सतह के नीचे निगरानी, खोज और बचाव अभियान तथा कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। नौसेना ने कहा कि यह युद्धपोत 77 मीटर लंबा और 1490 टन से अधिक वजन वाला है।

कल्पमेधा

हमें जो मिलता है, हम उससे जिंदा रहते हैं। परंतु हम जो देखते हैं, उससे हम अपनी जिंदगी बनाते हैं।
– विंस्टन चर्चिल

मध्यस्थता नामंजूर

कश्मीर मसले समेत पाकिस्तान से जुड़े अन्य मुद्दों पर भारत का रुख हमेशा से द्विपक्षीय बातचीत पर केंद्रित रहा है। किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र और कुछ अन्य देशों की ओर से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश की जाती रही है, लेकिन भारत ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। पिछले दिनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'आपरेशन सिंदूर' से सहमे पाकिस्तान ने भारत पर हमले का नाकाम प्रयास किया था। मगर, इससे पहले कि कार्रवाई तेज होती, दोनों देशों की सहमति से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर यह दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता की बदौलत ही भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो पाया है। भारत ने इस दावे को तत्काल खारिज कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के आग्रह पर ही भारत ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है।

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सबसे पहले घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने दस मई को सोशल मीडिया के जरिए की थी। उन्होंने यह दावा भी किया था कि संघर्ष रोकने पर सहमत न होने पर उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार रोकने की चेतावनी दी थी। इसके बाद ट्रंप ने कई बार इस दावे को दोहराया कि अमेरिका ने ही दोनों देशों को संघर्ष विराम के लिए राजी किया। हालांकि, ट्रंप के दावे से पैदा हुई भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने कई दफा स्पष्ट किया कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है।

अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में जी-7 देशों के सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। मगर, इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच सम्मेलन से इतर बातचीत नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री ने बीते मंगलवार को ट्रंप से फोन पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के मुताबिक, इस दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हुए संघर्ष पर भी बात हुई और प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बिना किसी मध्यस्थता के अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाई रोकी थी। मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और न कभी स्वीकार करेगा। यह भी साफ किया जा चुका है कि अब आतंकवाद को छद्म युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक युद्ध के ही रूप में देखा जाएगा। इसमें दोराय नहीं है कि आपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई नपी-तुली, सटीक तथा तनाव को और बढ़ावा नहीं देने वाली थी। भारत का यह रुख निस्संदेह पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि अगर वह द्विपक्षीय मसलों में किसी तीसरे पक्ष को बीच में लाने का प्रयास करेगा, तो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सेहत की चिंता

यह लापरवाही नहीं तो और क्या है कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल दिल्ली ने राष्ट्रीय वायु स्वच्छता कार्यक्रम के तहत मिली राशि का एक तिहाई से भी कम खर्च किया है। ऐसे में यहां स्वच्छ वायु की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अगर यहां के बाशिंदों को साफ हवा नहीं मिलती है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदूषण और तापमान का जनजीवन पर संयुक्त प्रभाव वास्तव में चिंता का विषय है। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी और प्रदूषण का एक साथ होना सुरक्षित प्राकृतिक हवा के अवसरों को सीमित कर देता है। सीईपीटी विश्वविद्यालय और जलवायु प्रौद्योगिकी कंपनी की इस अध्ययन रपट को हमें गंभीरता लेना होगा। इसमें कहा गया है कि दिल्ली में हर वर्ष लगभग 2,210 घंटे ऐसे होते हैं, जब तापमान 18 से 31 डिग्री के बीच रहता है। इस दौरान 1,951 घंटे ऐसे होते हैं, जब वायु गुणवत्ता खराब होती है। यानी 259 घंटे ही लोगों को साफ हवा मिल पाती है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का नागरिकों की सेहत पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो दूसरी ओर असहज तापमान के जोखिम से भी बचना है। कुछ शहरों की स्थिति दिल्ली से बेहतर जरूर हो सकती है, लेकिन भविष्य में वहां भी यही समस्या गहराने वाली है। लिहाजा, इन परिस्थितियों में जीने की आदत डालने के बजाय इस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ नए उपाय करने होंगे। ऐसे सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि घर इस तरह से बनाए जाएं, जहां ऊर्जा की बचत के साथ हवा का बेहतर प्रवाह हो। सेहत और सुकून के लिए अब जरूरी है कि शहरों और महानगरों में मौसम के अनुकूल नए भवन बनें और पुराने घरों में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था हो। इससे स्वच्छ हवा अधिक मिल सकेगी। इस दिशा में गंभीरता सोचने का वक्त आ गया है।

हिमनदों के अस्तित्व पर बढ़ता संकट

हिमनदों का पिघलना केवल बर्फ की मात्रा में कमी का मामला नहीं है। यह जलवायु तंत्र की जटिलता, पारिस्थितिकी संतुलन, जल स्रोतों की स्थिति, कृषि उत्पादन, विद्युत आपूर्ति और मानवीय जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ मसला है।

देवेंद्रराज सुथार

हिमनदों का तेजी से पिघलना आज सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुका है। यह केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव विश्व के प्रत्येक कोने में देखा जा सकता है। हाल ही में एक विज्ञान शोध पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है विश्व भर में दो लाख से अधिक हिमनदों की स्थिति का आकलन करने पर पता चला है कि अब ये पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। इस अध्ययन में अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर आठ विभिन्न जलवायु प्रतिरूपों का सहारा लिया और भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाया। इसी दौरान ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इस मुद्दे पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया। इससे पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है।

मानव सभ्यता ने जब से औद्योगीकरण की ओर कदम बढ़ाया है, तब से प्रकृति का संतुलन निरंतर प्रभावित होता चला गया है। कारखानों की स्थापना, ईंधन के अत्यधिक उपयोग और बेतहाशा वृक्षों की कटाई ने धरती के तापमान को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आज धरती का औसत तापमान औद्योगिक युग की शुरुआत की तुलना में लगभग डेढ़ डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। देखने में यह वृद्धि बहुत छोटी प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक है। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि यह तापमान दो डिग्री के भीतर नियंत्रित नहीं किया गया, तो इस सदी के अंत तक तीन चौथाई हिमनद पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं। और यदि तापमान को डेढ़ डिग्री तक सीमित रखने में भी सफलता मिलती है, तब भी लगभग आधे हिमनद समाप्त हो जाएंगे।

इन हिमनदों का पिघलना केवल हिम की मात्रा में कमी का मामला नहीं है। यह जलवायु तंत्र की जटिलता, पारिस्थितिकी संतुलन, जल स्रोतों की स्थिति, कृषि उत्पादन, विद्युत आपूर्ति और मानवीय जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ संकट है। जैसे-जैसे हिमनद पिघलता है, उसका जल पहाड़ और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचता है। इससे समुद्र का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति के अनुसार, वर्तमान में समुद्र का जलस्तर हर वर्ष लगभग चार मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, जो दीर्घकाल में विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। यह बढ़ता जलस्तर तटीय शहरों, द्वीप राष्ट्रों और समुद्र किनारे बसे लाखों लोगों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

दक्षिण एशिया और विशेषकर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमा व मालदीव जैसे देशों पर इसका सीधा प्रभाव देखा जा सकता है। बांग्लादेश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि समुद्र उनकी बस्तियों को निगलता जा रहा है। मालदीव जैसे देशों का भविष्य अनिश्चितता में पड़ गया है। क्योंकि वे समुद्र तल से कुछ ही मीटर ऊपर स्थित हैं। भारत के बड़े

तटीय नगर जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नवी मुंबई में वर्ष दर वर्ष समुद्री जल का अतिक्रमण बढ़ रहा है। वहां के लोगों को अब प्रत्येक वर्ष बाढ़, जल भराव और भवनों के कमजोर होने जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है।

> हिमनद केवल बर्फ के पहाड़ नहीं हैं। वे जीवन के स्रोत हैं। वे नदियों का उद्गम और पृथ्वी का संतुलन हैं और कृषि, जल, ऊर्जा व जैव विविधता का मूल आधार हैं। यदि हम उन्हें बचा पाए तो अपनी पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। यदि नहीं, तो विनाश की आहट भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में ही सुनाई देने लगेगी। यह केवल एक सूचना नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। यदि हम आज भी जाग जाएं और सशक्त निर्णय लें, तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। यदि हम उदासीन रहे, तो हिमनदों का लुप्त होना केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भूल बन जाएगा।

संकट का एक बड़ा भाग हिमालय क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का उद्गम इन्हीं हिमालयी हिमनदों से होता है। दक्षिण एशिया के लगभग दो अरब लोग इन नदियों के जल पर अपनी जीविका, कृषि, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए निर्भर हैं। यदि हिमनदों का पिघलना इसी प्रकार जारी रहा, तो नदियों का प्रवाह प्रभावित होगा, जिससे खाद्य उत्पादन कम होगा, बिजली की आपूर्ति बाधित होगी और लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हिमनद के पिघलने से नदियों में जल का प्रवाह असमान हो जाता है। गर्मियों में अधिक पानी आता है, जबकि सर्दियों और सूखे के मौसम में जल की मात्रा कम हो जाती है। यह असमानता बाढ़ और सूखे दोनों की संभावना को बढ़ा देती है। कई बार हिमनदों के नीचे झीलें बन जाती हैं और जब ये अचानक फटती हैं, तो जलप्रलय की स्थिति पैदा होती है। उत्तराखंड में कुछ वर्ष पूर्व ऐसी ही घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। नेपाल में भी इसी प्रकार की आपदाएं सामने आती रही हैं। इस संकट के मूल में यदि कोई कारण है, तो वह है मनुष्यों की लापरवाही और भौतिकवादी प्रवृत्ति।

जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई, तेज गति से बढ़ता औद्योगीकरण व शहरीकरण, प्रकृति के प्रति असंवेदनशील विकास नीति और उपभोगवादी जीवनशैली ने वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। हिमालय की भूमिका विशेष इसलिए भी है, क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां केवल भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी जीवनदायिनी हैं। जब इन नदियों का प्रवाह बाधित होगा, तो सीमा पार संबंधों में भी तनाव बढ़ेगा। जल संकट पर संघर्ष की संभावना बढ़ेगी। नदियों पर बनाए गए बांध और जलाशयों की उपयोगिता पर भी सवाल उठेंगे। विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्योंकि उन्होंने ही सबसे अधिक प्रदूषण फैलाया है। उन्हें विकासशील देशों की सहायता करनी होगी, जिससे वे स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा सकें। वैज्ञानिक शोध, सतत निगरानी और तकनीकी विकास इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

हिमनद केवल बर्फ के पहाड़ नहीं हैं। वे जीवन के स्रोत हैं। वे नदियों का उद्गम और पृथ्वी का संतुलन हैं। वे कृषि, जल, ऊर्जा और जैव विविधता का मूल आधार हैं। यदि हम उन्हें बचा पाए तो अपनी पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। यदि नहीं तो विनाश की आहट केवल भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में ही सुनाई देने लगेगी। यदि हम आज भी जाग जाएं और सशक्त निर्णय लें, तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। यदि हम उदासीन रहे, तो हिमनदों का लुप्त होना केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक भूल बन जाएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम कहेंगे कि हमने कभी हिमालय की गोद में जमी शांति को देखा था और आज वहां केवल सूखा पत्थर और बहता पानी रह गया है। इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार, समाज, विज्ञान और जनमानस मिल कर इस चुनौती का सामना करें।

बुलंद हौसले

दुनिया मेरे आगे

राजेंद्र बज

अगर हौसले बुलंद हों तो सारी कायनात हमारे सुर में सुर मिलाने लगती है। अंतर्मन में उत्साह का संचार सफलता की पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। किसी नेक काम को करने के इरादे से आत्मबल इतना सशक्त हो जाता है कि असंभव शब्द कहीं पीछे छूट जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी मन, वचन और कर्म की एकाग्रता से सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास पुरुषों का विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान इसका उदाहरण है। ठेठ आखेट युग से आज के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक दौर तक की विकास यात्रा यों ही पूर्ण नहीं हो सकी है।

अगर कुछ कर गुजरने का जुनून और दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो उल्लेखनीय सफलता हासिल करना कठिन नहीं है। मानव सभ्यता के विकास का क्रम भी इसी के सहारे आज की उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सका है। यह सिलसिला आज भी जारी है और आगे भी चलता रहेगा। आगे बढ़ने की चाहत के साथ कठिन रास्तों को तय करने वाले लोगों के उदाहरण हमें अपने आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम अपनी दृष्टि जितनी विशाल करेंगे, उतनी ही महान शख्सियत के बारे में जान पाएंगे। वैसे भी आजकल के दौर में असंभव तो कुछ भी नहीं रह गया है। यह सब हौसलों की बुलंदी का ही परिणाम है कि कल तक जो कल्पना से भी परे था, आज सहज संभव नजर आने लगा है। ऐसा नहीं है कि यह सब पलक झपकते ही संभव हो गया हो। हौसला मतलब- हिम्मत, हर व्यक्ति के अंदर यह छिपी हुई शक्ति होती है, जिसका खुद को एहसास करना होता है। जो कार्य हम आसानी से करने की उम्मीद नहीं रखते और कोई दूसरा उसे अंजाम तक पहुंचाता है तो वह उसका हौसला ही है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है।

> हौसला मतलब- हिम्मत, हर व्यक्ति के अंदर यह छिपी हुई शक्ति होती है, जिसका खुद को एहसास करना होता है। जो कार्य हम आसानी से करने की उम्मीद नहीं रखते और कोई दूसरा उसे अंजाम तक पहुंचाता है तो वह उसका हौसला ही है। यानी उस व्यक्ति ने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है।

दरअसल, तमाम तरह के विकास के कारक तत्त्वों में बड़े से बड़ा जोखिम उठाने का माद्दा सन्निहित है, जिसके परिणामस्वरूप निरंतर अनुसंधान कार्यों के साथ-साथ वृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना संभव हुई है। व्यवसाय का तेज गति से विस्तार हुआ। रोजगार के नए-नए आयाम स्थापित होने लगे और आम नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुधार हुआ। दुनिया भर में तरक्की की रफ्तार निरंतर तेज होती जा रही है। कल तक हमारा देश कृषि प्रधान होने के बावजूद खाद्यान्न पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर रहा करता था, लेकिन देखते ही देखते हर एक क्षेत्र में बुलंद हौसले के साथ हम आगे बढ़ते रहे। इस स्थिति के मूल में राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ व्यापार व्यवसाय, शिक्षा एवं चिकित्सा जगत के पुरोधाओं का बुलंद हौसला ही था, जिसकी बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम लेने की क्षमता का विस्तार हुआ। दरअसल, हर एक क्षेत्र में बड़े लक्ष्य को सामने रख कर कार्य योजनाएं बनाई गईं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए।

आज हम शहरी परिवेश को देखें या ग्रामीण, हर तरफ आमूल परिवर्तन की स्थिति दिखाई देती है। शहर और अधिक विकसित हो रहे हैं, तो विभिन्न नगर, गांव एवं कस्बों में भी आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार देखा जा सकता है। तकनीक घर-घर दस्तक दे चुकी है, नागरिकों की बौद्धिक क्षमता बढ़ी है। कृषि कार्य का आधुनिकीकरण हो गया है, व्यापार व व्यवसाय का स्वरूप भी बदल गया है। आज हर क्षेत्र में देश की विकासात्मक तस्वीर साफ देखी जा सकती है। यह सब दशकों की लंबी साधना का परिणाम है, जो हौसले से ही संभव हो सका है। सफलता के लिए सिर्फ प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, इसके लिए सही कदम उठाने के साथ सोच में स्पष्टता और बुलंद इरादा भी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति और हालात से मुकाबला करने का साहस हो तो फिर कोई भी ताकत लक्ष्य को हासिल करने से डिगा नहीं सकती।

बदलते वक्त के साथ व्यक्ति विशेष की जीवन शैली में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। समाज विशेष की जीवन शैली में परिवर्तन भी स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन करोड़ों नागरिकों की जीवन शैली में व्यापक बदलाव यूं ही नहीं आ जाता। इसके लिए कई मोर्चों पर बुलंद हौसलों की जरूरत पड़ती है। व्यापक स्तर पर जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है और इस क्षमता को सही दिशा देकर सकारात्मक परिणाम पर केंद्रित कर लक्ष्य को पाना होता है। सकारात्मक सोच के साथ अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की और अधिक इच्छाशक्ति जागृत करना बुलंद हौसलों की पहचान है। अपनी कमजोरी या लाचारी को लेकर किसी और को दोष देने की बजाय अपने आत्मबल को मजबूत बनाने की दिशा में विचार करना चाहिए। देश-दुनिया के हर एक क्षेत्र में जितने भी सफलतम व्यक्तित्व हैं, गहराई से देखें तो उनके लिए परिस्थितियां कभी भी आसान नहीं थी। उनकी सफलता के पीछे उनके बुलंद हौसलों का बड़ा हाथ रहा है।

युद्ध के जोखिम

संपादकीय 'युद्ध के बादल' (16 जून) पढ़ा। ईरान-इजराइल संघर्ष शुरू हो चुका है। हर देश को आत्मरक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का अधिकार है। इसी कड़ी में परमाणु संयंत्रों के निर्माण में ईरान या कोई देश संलग्न है, तो दूसरे को चिंतित होने की जरूरत क्यों है। इस संबंध में जब संयुक्त राष्ट्र ने कोई आचार संहिता नहीं बनाई है, तो सवाल यह है कि इजराइल आखिर क्यों भयभीत है। परमाणु संपन्न मामले में महाशक्तियों की यह मनमानी है कि कोई उनकी बराबरी न करे। क्योंकि, इससे उनको चुनौती दी जा सकती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आज दुनिया परमाणु विस्फोट के मुहाने पर है। परमाणु बम बनाने के बजाय देश यदि अपने यहां गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी और कुपोषण के समाधान पर ध्यान दें, तो वे समावेशी विकास की ओर बढ़ेंगे। रूस-यूक्रेन के बाद इजराइल-ईरान युद्ध का पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। इससे महंगाई और तमाम वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला प्रभावित होगी।

– अशोक कुमार, पटना, बिहार

हादसों के पुल

पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल पिछले दिनों अचानक गिर गया। देश में कई पुल जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में इस तरह के और भी हादसे हो सकते हैं। पुलों के गिरने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। कहीं रखरखाव के अभाव में, तो कहीं निर्माण के दौरान और उद्घाटन के बाद भी पुल गिरते रहे हैं। इसकी एक वजह घटिया सामग्री तो है ही, वहीं गुणवत्ता की समय-समय पर जांच न होने से भी ठेकेदारों को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। इसमें सरकारी महकमों की भी लापरवाही रहती है। सड़कों का निर्माण हो या पुलों का अथवा इमारतों या अन्य सरकारी कार्यों का, इसमें सुधार आवश्यक है। देश में नवनिर्माण तो तेजी से हो रहे हैं, लेकिन पुराने पुलों और सड़कों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिए।

– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

मुश्किल में छात्र

ईरान और इजराइल युद्ध से एक बड़ा खतरा भारतीय छात्रों और प्रवासियों पर मंडरा रहा है। ईरान में करीब 3000 भारतीय छात्र हैं और बड़ी संख्या में प्रवासी भी हैं। जम्मू-कश्मीर में इन छात्रों के परिवारों ने राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया कि केंद्र से सहयोग लिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि युद्ध पर नजर रखी जा रही है और छात्रों तथा प्रवासियों को सुरक्षित निकालने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इजराइल में भी बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने जाते रहे हैं। यदि युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो उन्हें वहां से निकालना पड़ेगा। विश्व समुदाय यदि इस युद्ध को समाप्त नहीं कराता है, तो पूरी दुनिया में अशांति और तनाव का माहौल बन सकता है। जहां ईरान अंतिम दम तक लड़ाई की बात करता है, तो इजराइल उसे बर्बाद करने का दावा कर रहा है।

– बीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

जवाबदेही की दरकार

संपादकीय 'लापरवाही की परतें' (17 जून) पढ़ा। पिछले दिनों कुछ हादसे नियमों की अनदेखी तथा कानूनों के पालन में लापरवाही के कारण हुए। देश में भगदड़ के कारण जानलेवा हादसों तथा रेल दुर्घटनाओं को लेकर भी इसी प्रकार का वातावरण बना था, परंतु ऐसा लगता है कि लापरवाही प्रशासनिक तंत्र का चरित्र बन गया है। कोई भी दुर्घटना होने पर कुछ दिन चर्चा गर्म रहती है। परंपरागत रूप से ऐसे हादसों की गहन जांच होती है, लेकिन दुर्भाग्य से जांच के निष्कर्ष कभी-कभार ही सार्वजनिक किए जाते हैं। हादसों के लिए जवाबदेही तय नहीं होती है। इसी लापरवाही के कारण हम अगली किसी और दुर्घटना की प्रतीक्षा करने लगते हैं। यदि देश में 'सब चलता है' की संस्कृति रहेगी, तो फिर लापरवाही भी कायम रहेगी।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

कनाडा में दो-टूक

पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दावत में शरीक होने की तैयारी कर रहे थे, उसके कुछ ही समय पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-पाक संघर्ष व आतंकवाद के बारे में जो कुछ कहा, उससे यकीनन पाकिस्तान और मुनीर के मनसूबों पर पानी फिर गया होगा। बल्कि वाशिंगटन को भी यह एहसास हो गया होगा कि राजनय में बड़बोलापन एक बुराई है और इससे बचा जाना चाहिए। गौरतलब है, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाकिस्तान के संघर्ष को उन्होंने हस्तक्षेप करके रुकवाया। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने दो-टूक शब्दों में राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न ही करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दोनों शासनाध्यक्षों की इस बातचीत का ब्योरा पेश करते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी स्तर पर अमेरिका से ट्रेड डील या मध्यस्थता को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। इस विवाद के पटाक्षेप के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल माकूल जगह और वक्त चुना है। उनके उत्तर से कनाडा में जुटे तमाम ताकतवर देशों के शासनाध्यक्षों पर भी भारत का रुख जाहिर हो गया है। साथ ही, घरेलू स्तर पर भी सीजफायर को लेकर उन्हें घेरने की विपक्ष की कोशिशें कमजोर होंगी।

भारत-पाक संघर्ष-विराम में राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता-विवाद के पटाक्षेप के लिए प्रधानमंत्री ने माकूल समय चुना। इससे पूरी दुनिया पर भारत का रुख जाहिर हो गया।

जी-7 की बैठक में भाग लेने कनाडा के कनानास्किस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी याद किया जाएगा कि लंबे समय से भारत और कनाडा के द्विपक्षीय रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने का ठोस संकेत सामने आया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ओटावा और नई दिल्ली में उच्चायुक्तों की बहाली पर अपनी सहमति जताई है। दोनों ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से जंग में सहयोग पर भी एकमत जाहिर किया है। विडंबना यह है कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ही दोनों के रिश्ते राजनयिकों को निष्कासित करने के कटु मोड़ तक पहुंच गए थे। बहरहाल, यह कोई ढकी-छिपी बात नहीं है कि कनाडा के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप के तल्ख तेवर ने उसे अधिक व्यावहारिक रुख अपनाने को प्रेरित किया है। उसके नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ एआई और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जताई है, तो भारत ने भी आपसी रिश्तों के महत्व को रेखांकित किया है। मगर ओटावा को भारत की चिंताओं को समझना होगा। खालिस्तानी आतंकियों को वहां से मिलने वाले खाद-पानी पर रोक में दोनों देशों के मधुर रिश्तों की चाबी है।

वैसे भी, विश्व राजनय में रिश्ते जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। आखिर पाकिस्तान की संप्रभुता को रौंदते हुए अमेरिका द्वारा एबटाबाद में की गई कार्रवाई को कितने साल बीते हैं? मगर एक बार फिर वाशिंगटन को इस्लामाबाद की मदद की दरकार आन पड़ी है, ताकि वह तेहरान को सबक सिखा सके। अमेरिका के इस दोहरेपन ने ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की धार कुंद की है। आसिम मुनीर को लंच पर बुलाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को ही उसकी हैसियत का एहसास नहीं कराया है, बल्कि हमारे पड़ोस में लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का भी काम किया है। खैर, भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि उसकी धरती पर यदि किसी ने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, तो उसे देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा।

हिन्दुस्तान Sindustan | 75 साल पहले 19 जून, 1950

बिना टिकट रेल-यात्रा

बिना टिकट रेल-यात्रा करने का रोग हमारे देश में पिछले वर्षों में काफी फैला है। रेल मंत्रालय ने बिना टिकट रेल यात्रा के संबंध में एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की है, उससे इस रोग की गंभीरता सहज ही ज्ञात हो जाती है। उसमें बताया गया है कि सन् 1948-49 में बिना टिकट रेल-यात्रा करने वाले 60 लाख व्यक्ति पकड़े गये और उनसे डेढ़ करोड़ रुपया वसूल किया गया। वस्तुतः बिना टिकट सफर करने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक होगी; क्योंकि बिना टिकट सफर करने वाले सभी पकड़ में नहीं आते।

जो लोग टिकट खरीदकर सफर करते हैं। उनके मन में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि बिना टिकट सफर करने वालों के मुकाबले ये अल्पमत में हैं अथवा बहुमत में। आप किसी गाड़ी से सफर कीजिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो हर स्टेशन पर आप ऐसे लोगों को उतरते देखेंगे, जिन्होंने टिकट नहीं खरीदा होगा। ये खुले तौर पर रेल के तारों को लांघकर निकल जाते हैं और कोई रेल-कर्मचारी उन्हें रोकता नहीं। जहां रेलवे के प्रबन्ध में इतनी शिथिलता हो, वहां बिना टिकट रेल-यात्रा करने वालों को तादाद काफी बड़ी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मनुष्य स्वभाव से कमजोरी का पुतला होता है। जब वह देखता है कि मुफ्त में रेल की सैर की जा सकती है, तो व्यर्थ ही जेब से पैसा क्यों खर्च किया जाये? पैसे के लोभ के आगे वह अपने समस्त नैतिक और सामाजिक दायित्व को भूल जाता है।

आखिर बिना टिकट रेल-यात्रा करने के रोग के प्रसार पाने के कारण क्या हैं? एक कारण तो यह है कि पिछले वर्षों में रेलयात्रियों की संख्या बराबर बढ़ती गई है। युद्ध के वर्षों में और उसके बाद कम से कम तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए आराम से सफर करना असंभव हो गया है। गाड़ियों के डिब्बों में इन्सान भेड़-बकरियों की तरह ठुंस जाते हैं। यात्री अगर पिसने-कुचलने से बच जाये, और बिना अपना माल-असबाब खोये सकुशल अपने स्थान को पहुंच जाये तो अपने को परम सौभाग्यशाली समझेगा। जहां इतनी भीड़-भाड़ और धक्कामुक्की हो, वहां कैसे तो आदमी टिकट खरीदे और कैसे कोई चेक करे। सन् 1938 में 53 करोड़ 10 लाख यात्रियों ने रेलों से सफर किया, 1948-49 में यह संख्या 118 करोड़ तक पहुंच गई।

ट्रंप-मुनीर मुलाकात के गहरे मायने

अश्विनी महापात्रा | प्रोफेसर, जेएनयू

वास्तव में अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी दुश्मन नहीं समझा। वह वाशिंगटन के लिए सामरिक दृष्टि से फायदेमंद रहा है। अमेरिका को यह फायदा फिर उससे लेना है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी जनरल व फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। व्हाइट हाउस में लंच पर हुई मुलाकात का मतलब गहराई से समझना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इजरायल-ईरान संघर्ष में अमेरिका कूदना चाहता है। जब वह संघर्ष में कूदेगा, तो उसे पाकिस्तानी एयर बेस की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप-मुनीर मुलाकात की पहली और सामरिक वजह यही है।

दूसरी वजह रणनीतिक है। ईरान के खिलाफ जब अमेरिका उतरेगा, तो एक खतरा यह है कि मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे। ऐसे में, पाकिस्तान को साथ रखने में अमेरिका का अपना हित है। दुनिया में यह संदेश जाएगा कि पूरी मुस्लिम दुनिया ईरान के साथ नहीं है। तीसरी वजह कूटनीतिक है। जब ईरान में शासन बदलेगा, वहां जो नया शासन आएगा, उसमें भी मुस्लिम देशों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में, पाकिस्तान को साथ रखने में अमेरिका अपना फायदा देख रहा है।

हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी भी दुश्मन नहीं समझा। पाकिस्तान वास्तव में अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से काफी फायदेमंद रहा है। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति का सामरिक फायदा अमेरिका दशकों से उठाता आया है। इसके अलावा, पाकिस्तान मुस्लिम देश होने के साथ ही एक कमजोर राष्ट्र है। वह भारत की तरह मजबूत या लोकतांत्रिक नहीं है। पाकिस्तान को उसका सैन्य प्रतिष्ठान चलाता है। जब आप सीधे पाकिस्तानी सेना को पकड़ते हैं, तो आपका मनचाहा काम ज्यादा आसानी से हो जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक नेता न तो मजबूत होते हैं और न उनकी देश में कोई ज्यादा भूमिका होती है। पाकिस्तानी सेना को अमेरिका का साथ देने से फायदा भी होता आया है। उसे पैसा, सैन्य मदद भी मिलती है। मजहबी कट्टरता की बुनियाद पर पाकिस्तानी सेना आतंकियों को खड़ा करती है, पर जिस आतंकी से अमेरिका को समस्या होती है, उसे बहुत सहजता से अमेरिका के हवाले कर दिया जाता है। यह साफ समझ लेना चाहिए कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान से सौदेबाजी अमेरिका के लिए आसान है। अतः मुनीर-ट्रंप मुलाकात कतई चौंकाती नहीं है।

कल को जब ईरान में दखलंदाजी की वजह से अमेरिका विरोधी माहौल बनेगा, तब मुस्लिम देश पाकिस्तान ही उसके काम आएगा। ट्रंप इस काम के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को बुला सकते थे, पर वह जानते हैं कि असल में जनरल मुनीर ही अमेरिका के ज्यादा काम आएंगे। अभी आतंकवाद अमेरिका के लिए मसला नहीं है। अभी उसका एक लक्ष्य है, ईरान को परमाणु बम से लैस होने से रोकना। इजरायल बार-बार कह रहा है कि रोका न गया, तो ईरान जल्दी ही परमाणु बम बनाकर सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि इजरायल हमलावर हो गया है। इजरायल और अमेरिका, दोनों जानते हैं कि अभी सऊदी अरब से कतर और पाकिस्तान तक, हर मुस्लिम देश में इजरायल से नाराजगी है।

भले ही पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान परोक्ष रूप से अमेरिका की मदद कर रहा हो, पर आप पाकिस्तान के टीवी प्रसारणों पर नजर फेरिए, जहां लगातार इजरायल के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। यह पाकिस्तान की बड़ी विडंबना है। पाकिस्तान में अमीर ही नहीं, गरीब भी इजरायल के खिलाफ हैं, पर यह देश इजरायल के खिलाफ नहीं जा पाएगा। अमेरिका हमेशा की तरह बहुत तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने हित में करेगा। वहां अमेरिकी विमान उतरेंगे, ठहरेंगे, ईंधन भरेंगे और हमले के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को इसीलिए व्हाइट हाउस लंच पर बुलाया गया और वह अमेरिका की बात सहर्ष मान लेंगे।

मुनीर जानते हैं कि अभी मौका है, अगर अभी अमेरिका की मदद करेंगे, तो भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका से गुहार लगा सकेंगे। भारत के साथ पाकिस्तान के अनेक मसले हैं, सबसे बड़ा मसला सिंधु जल का है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अमेरिका आगे बढ़कर भारत पर पाकिस्तान के मुताबिक बातचीत के लिए दबाव डालेगा। पाकिस्तान को तो भारत के खिलाफ अपनी बात रखने का मौका मिल गया। ऐसी स्थिति पहले भी अनेक बार बनी है।

भारत को तात्कालिक रूप से नुकसान तो होगा, लेकिन अब यह हमारी कूटनीति पर निर्भर करता है कि हम इस विडंबना या समस्या से कैसे निपटते हैं। हमें ईरान-इजरायल संघर्ष से कोई नुकसान न हो, इसके लिए हमारे कूटनीतिज्ञों को अपनी योग्यता का परिचय देना होगा। गौर करने की बात है कि भारतीय कूटनीति पर दबाव है। ऑपरेशन सिंदूर को भी एक तरह से दबाव में ही खत्म किया गया। हमारी कूटनीति दबाव में न आए, यह हमें सुनिश्चित करना होगा।

फिलहाल, विश्व परिदृश्य में भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। हम जानते हैं कि इजरायल हमारा मित्र है। जब भी भारत पर हमला होता है, इजरायल अकेला देश है, जो खुले रूप से भारत का समर्थन करता है। कूटनीतिक, रणनीतिक और सामरिक, तीनों ही स्तर पर इजरायल भारत की मदद करता रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत कभी इजरायल के खिलाफ जाएगा, पर खुलकर इजरायल का समर्थन भी नहीं करेगा। यह तय है कि भारत युद्ध नहीं चाहता। दुनिया के अनेक देश युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उनके चाहने या न चाहने का ज्यादा अर्थ नहीं है।

बड़ी बात यह है कि इजरायल संघर्ष चाहता है। 7 अक्तूबर के हमले के बाद से ही इजरायल अपने दुश्मनों को मिटाने में लगा है। उसने हमास, हिजबुल्ला जैसे अनेक दुश्मन संगठनों को कमजोर कर दिया है। ऐसे तमाम संगठनों को इजरायल ने कमजोर कर दिया है, जो कभी ईरान के साथ खड़े थे या जिनकी मदद ईरान खुलकर करता था। यह मौका है, जब ईरान कमजोर और अकेला है, तो इजरायल यह मौका क्यों छोड़ेगा? ईरान सैन्य शक्ति है, पर उसके ज्यादातर विमान बीस साल पुराने हैं। वह इजरायल के सामने टिक नहीं पा रहा है। अतः इजरायल के लिए यह मौका है कि वह ईरान को निकट भविष्य में परमाणु शक्ति बनने से रोक दे।

भारत और दुनिया के सजग देशों की ओर से सबसे बेहतर कोशिश यही होगी कि यह संघर्ष जल्दी से जल्दी थम जाए। आम लोग न मारे जाएं, एशिया में अशांति न बढ़े। ईरान और इजरायल के बीच संवाद हो, सम्मानजनक समझौता हो, ताकि दोनों फिर शांति से रह सकें। इसी दिशा में भारत को काम करना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अपने मोटे मुनाफे से शहरों को भी मदद करे क्रिकेट बोर्ड

नारायण रामचंद्रन | आर्थिक सलाहकार

क्रिकेट से जुड़ा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल लीग है। जी हां! आपने ठीक पढ़ा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लीग। एनएफएल के सामने हालांकि अभी यह 18 साल का बच्चा है। इसके मुकाबले अमेरिकी मेजर लीग बेसबॉल 125 साल से भी अधिक पुराना है, जबकि एनएफएल 100 साल और फॉर्मूला वन का 75 साल का इतिहास है।

कमाई के मामले में एनएफएल हर स्तर पर सबसे ऊपर है। इसकी कुल आय लगभग 20 अरब डॉलर है, जबकि इसकी हरेक टीम की कमाई 60 करोड़ डॉलर और प्रति मैच 6.7 करोड़ डॉलर है। आईपीएल की प्रति मैच कमाई लगभग 1.7 करोड़ डॉलर (लगभग डेढ़ अरब रुपये) है और यह दूसरे स्थान पर आता है। एनएफएल जैसे प्रमुख खेल लीगों के मुकाबले काफी नया होने के बावजूद आईपीएल का राजस्व 20 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है, जबकि एनएफएल की वार्षिक वृद्धि दर आठ से दस प्रतिशत ही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) आईपीएल लीग का मुखिया है। वह एक करमुक्त संगठन है, जो इस पूरे मनोरंजन को नियंत्रित करता है।

बीसीसीआई अपने भारी मुनाफे से कुछ खर्च करे और ऐसी जगहों पर स्टेडियम बनवाए, जो सार्वजनिक परिवहन से बेहतर जुड़ी हों।

दुनिया भर के बड़े खेल लीगों की तरह आईपीएल की कमाई भी टीवी-डिजिटल अधिकार, प्रायोजकों, स्टेडियम के टिकटों और दूसरे तरह के व्यावसायों से होती है। मसलन, बीसीसीआई ने साल 2023 से 2027 तक के लिए डिज्नी/वायकॉम 18 के साथ छह अरब डॉलर का टीवी डिजिटल अधिकारों को करार किया है। सालाना 1.2 अरब डॉलर की इस आय के अलावा, बोर्ड केंद्रीय प्रायोजन से 10 से 20 करोड़ डॉलर तक की कमाई कर लेता है। बीसीसीआई इसका आधा हिस्सा दस फ्रेंचाइजी टीमों को दे देता है। इस तरह प्रत्येक फ्रेंचाइजी टीम को सीधे बोर्ड से लगभग छह करोड़ डॉलर और अपने स्तर पर एक करोड़ डॉलर की कमाई होती है।

आईपीएल को एक चमत्कारिक आयोजन बनाने में देश की कई चीजें मददगार हैं। जैसे, भारत की विशाल आबादी में क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप के प्रति हद दर्जे का जुनून है। आईपीएल प्रशंसकों में 40-50 फीसदी महिलाएं हैं, जिससे विज्ञापन बाजार को विस्तार मिलता है। विराट कोहली जैसे कुछ सितारों के पास तो इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर 28 करोड़ का विशाल फॉलोअर समूह है। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या कोहली से ज्यादा है।

भारत में आईपीएल खिलाड़ियों को नीलामी में मिलने वाली भारी रकम हैरान करती है, क्योंकि दुनिया भर के अन्य प्रमुख लीगों की तुलना में आईपीएल की 'प्रतिभा लागत' सबसे कम है। इस लीग की एक अच्छी बात यह है कि साल 2027 में मीडिया अधिकारों की अगली नीलामी के तुरंत बाद शायद टीमों की संख्या और खेल के सत्र बढ़ेंगे। मेरा अनुमान है कि अगले दस वर्षों में आईपीएल में मीडिया अधिकारों की कीमत 1.2 अरब डॉलर सालाना से लगभग 10-12 गुना तक बढ़ सकती है। बीसीसीआई इससे सालाना पांच अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई करेगा। गौर कीजिए, बोर्ड इस कमाई पर कोई कर नहीं अदा करता है। अपने शुरुआती दिनों में आईपीएल 'मैच फिक्सिंग' से हिल गया था। इसकी सबसे बुरी बात तब यह सामने आई थी कि उन घोटालों में अंदर के लोगों का ही हाथ था। सौभाग्य से अब फिक्सिंग का खेल खत्म हो गया है। आज इसकी सबसे बुरी बात बेलगाम उपभोक्तावाद का समर्थन है। और इसका सबसे बदतर पहलू तो बेंगलुरु में दिखा, जब अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरसीबी के विजय के जश्न में 11 प्रशंसकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

आईपीएल के महाकुंभ में अगले कुछ वर्षों तक लगातार बढ़ोतरी का अनुमान है। इसलिए बीसीसीआई को चाहिए कि वह अपने बेतहाशा मुनाफे में से कुछ खर्च करे व ऐसी जगहों पर स्टेडियम बनवाए, जो सार्वजनिक परिवहन से बेहतर जुड़ी हों और आपदा रोधी हों। शहरी नियोजन में वह योगदान करे और इस पूरी योजना को इस तरीके से बनाए कि आईपीएल हर जगह अपने बेहतर रूप में दिखे, तभी इसका भरपूर आनंद लिया जा सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

पहले खुद को खोज लो

मनुष्य प्रश्न नहीं, बल्कि एक निरंतर खोज है। एक प्रश्न तो बुद्धि द्वारा हल किया जा सकता है, लेकिन एक खोज का समाधान अस्तित्वगत रूप से ही किया जाना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं, यह कुछ ऐसा है कि हम अपने अस्तित्व के लिए कुछ उत्तर खोज रहे हैं।

सदियों से मनुष्य अपनी ही खोज कर रहा है। वह जानता है कि वह है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे नहीं मालूम, वह कौन है? इसलिए जन्म लेने के साथ ही उसके आंतरिक गहनतम केंद्र में एक महान प्रश्न उठना शुरू हो जाता है। हम इस उठने वाले प्रश्न या खोज को दबा सकते हैं, उस खोज की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन उसे मार नहीं सकते। उसको मार देने या समाप्त कर देने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति में अंतर्निहित है। यह जानने की खोज उसकी चेतना में अंतर्निहित है कि वह आखिर है क्या?

यह खोज ही मनुष्य का प्रामाणिक स्वभाव है, और जब तक यह दृढ़ निश्चय न बन जाए, मनुष्य खोज करता रहता है। वास्तव में, इस संबंध में गलत दिशा में जाने के नौ सौ निन्यानबे रास्ते हैं और वहां जाने का केवल एक मार्ग ही ठीक मार्ग है, इसलिए यह खोज खतरों से भरी हुई है। यह साधारण खोज न होकर बहुत जटिल खोज है और मनुष्य बहुत कठिनाई से वहां पहुंच पाता है। लेकिन जब तक तुम पहुंचोगे नहीं, तुम पीड़ा और उपद्रव में पड़े रहोगे। तुम प्रचंड अव्यवस्था के मध्य रोते-चीखते रहोगे। तुम यह नहीं जान पाओगे कि प्रसन्नता क्या होती है? तुम स्वयं को न जान लो, तो फिर तुम कैसे प्रसन्न हो सकते हो? और तुम कैसे जान पाओगे कि कैसे होते हैं वे आशीर्वाद? बिना स्वयं को जाने परमात्मा के आशीर्वाद बरसते ही नहीं।

तुम 'संतोष' और 'परमानंद' जैसे शब्द सुनोगे, लेकिन वे केवल शब्द ही बने रहेंगे। उनके पास ऐसा कुछ न होगा, जो तुम्हें तृप्ति दे सके। यह संतुष्टि और तृप्ति तो तुम्हारे अनुभव ही तुम्हें देंगे। वे तो खाली शब्द बने रहेंगे। वे तुम्हारे चारों ओर एक शोर उत्पन्न करेंगे, लेकिन उनका कुछ भी अर्थ नहीं होगा।

यह खोज खतरों से भरी हुई है। यह साधारण न होकर बहुत जटिल खोज है और मनुष्य बहुत कठिनाई से वहां पहुंच पाता है। लेकिन जब तक तुम पहुंचोगे नहीं, तुम पीड़ा और उपद्रव में पड़े रहोगे।

खोज, मनुष्य का सहज स्वभाव है। लेकिन समस्या यह खड़ी हो जाती है कि गलत दिशा में जाने के लिए वहां अनेक रास्ते हैं, फिर ठीक मार्ग कैसे खोजा जाए? कार्लाइल ने कहा है, 'मनुष्य का दुर्भाग्य उसकी महानता के स्रोत में ही होता है। इसके लिए वहां उसमें कुछ चीज असीम होती है और वह पूरी तरह अपने आप को सीमित के हाथों में बेचने को सफल नहीं हो सकता।' मनुष्य के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, जो कहीं उच्चतर और महान है, खोज उसी की है।

ओशो

जे डी वेंस | अमेरिकी उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ट्रंप का साफ कहना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपनी टीम को ईरान से समझौता करने भी भेजा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यह काम या तो समझौते से होगा या फिर 'दूसरे तरीके' से।

अनुलोम-विलोम

छात्रों की वापसी

छात्रों की वापसी में हो रही देरी अक्षम्य

ईरान-इजरायल के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद इन दोनों देशों में पढ़ने या किसी अन्य काम से गए भारतीय नागरिक बुरी तरह से फंस गए हैं। संकट की इस घड़ी में उन्हें वहां सामान्य सुविधाएं, यहां तक कि भोजन सामग्री भी मुश्किल से मिल पा रही है। अंधाधुंध मिसाइल हमलों से उनका जीवन संकट में पड़ गया है। ऐसे में, उन्हें तत्काल वापस लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन देखा गया है कि तेहरान और इजरायल के शहरों से भारतीयों को वापस लाने में बहुत देर हुई है। संघर्ष शुरू होने के चार-पांच दिन के बाद ही वहां फंसे भारतीय नागरिकों की किसी तरह से वापसी शुरू हो पाई। वह भी दूसरे देशों की मदद से। संघर्ष के इतने दिनों के बाद खबर आई कि भारतीय वायु सेना ईरान में रह रहे भारतीयों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। वायु सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि ईरान में फंसे छात्रों को वापस लाने की तैयारी तेजी से की जा रही है। सेना पूरी तरह से तैयार है और केंद्र सरकार से निर्देश मिलते ही नागरिकों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी तब तक केंद्र की मंजूरी भी नहीं मिली थी। यह बहुत ही चिंताजनक बात है।

देश के नागरिकों, खासकर अपने छात्रों को तो इस तरह से अनाथ हालत में कई दिनों तक नहीं ही छोड़ा जाना चाहिए। ये वे छात्र हैं, जो देश में शिक्षा की भरपूर सुविधा न मिल पाने के कारण ही अपने खर्चे पर विदेश पढ़ने जाते हैं। इनमें से सब संपन्न परिवारों के ही हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे आस-पास के अनेक मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे यूक्रेन, ईरान, चीन, इजरायल, बांग्लादेश आदि देशों में सस्ती शिक्षा मिलने के कारण जाते हैं। इसका दुखद पहलू यह भी है कि हमारे देश में इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। स्थिति यह है कि जिस मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र यूक्रेन, रूस आदि देशों में 25 से 30 लाख रुपये खर्च करते हैं, उसके लिए देश में एक से डेढ़ करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि ये छात्र मजबूरी में ही दूसरे देशों में जाते हैं। सरकार को अपने देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। तब जाकर छात्रों का विदेश की ओर देखना बंद होगा। वे अपने देश में ही विदेश से सस्ती शिक्षा पाएंगे और उन्हें किसी संकट में पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार भी ऐसे युद्धों के समय निश्चिंत रहेगी। देश में विशेष तौर पर मेडिकल शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार सबसे पहले इन युद्धग्रस्त देशों में फंसे छात्रों को वापस लाने का प्रयास तेज करे, फिर शिक्षा का ऐसा प्रबंध किया जाए, जिससे छात्र दूसरे देश पढ़ने न जाने पाएं।

मुकेश ठाकुर, टिप्पणीकार

सरकार भारतीयों को वापस ला तो रही है

भारत से बड़ी संख्या में छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। इनके अलावा प्रवासियों की बड़ी संख्या दूसरे देशों में कमाने के लिए जाती है। लेकिन जब दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, तब भारतीय वहां संकट का सामना करते हैं और उनकी जान पर बन आती है। उनके परिवार चिंतित होते हैं और केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनके संबंधियों को शीघ्र वापस लाया जाए। ऐसे में, विदेश मंत्रालय सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी कूटनीतिक कौशल के अलावा संकट में फंसे भारतीयों को वापस लाने की भी होती है। उन-उन देशों में भारत के दूतावास पूरी क्षमता से कार्य करते हुए भारतीयों को वापस लाते हैं। हमें अपने विदेश मंत्रालय पर गर्व होना चाहिए, विशेष रूप से उन सभी दूतावासों पर, जिन्होंने संकट के समय हजारों की संख्या में भारतीयों को वापस देश भेजा है। पिछले दिनों यूक्रेन-रूस युद्ध के समय भी हजारों की संख्या में छात्रों/प्रवासियों को भारत लाया गया था, जिसमें वहां के राजदूतों और दूतावासों की बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार कुवैत से भी संकट काल में फंसे भारतीयों को निकाला गया था।

आज ईरान और इजरायल में हजारों की संख्या में हमारे छात्र और भारतीय मूल के लोग फंसे हुए हैं। उनके परिवार सरकार से संपर्क कर रहे हैं। बहुत से छात्रों को लाया गया है और बचे हुए को लाने की प्रक्रिया जोरों पर है। तेहरान से छात्रों को सुरक्षित ठिकानों पर लाया गया है और आने वाले दिनों में ये गतिविधियां तेज होंगी। ईरान और इजरायल से सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी भारत का विदेश मंत्रालय एवं संबंधित दूतावास पूरी सावधानी के साथ बखूबी निभा रहे हैं। अपेक्षा है कि सरकार के संबंधित मंत्रालय मिलकर काम करते हुए इस बड़ी चुनौती का सामना कर पाएंगे और सभी भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित कर पाएंगे।

हालांकि, इस काम में देश का बहुत धन खर्च होता है और संकट के समय व्यवस्था करना भी बहुत दुरूह कार्य हो जाता है। ऐसे में, इस पर भी सोचा जाना चाहिए कि अपने देश के नागरिकों को वापस लाने पर होने वाले खर्च का प्रबंधन किस तरह से किया जाए? यह खर्च संबंधित छात्र से लिया जाना एक विकल्प हो सकता है। क्योंकि छात्र सामान्य दिनों में आते हैं, तो अपना ही खर्च करते हैं, फिर इस विकट समय में भी वे अपना खर्च वहन करें और सरकार सुविधा उपलब्ध कराए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस मिशन में सरकार और हमारी एजेंसियां कामयाब होंगी।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 19-06-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: dilip.lal Time: 06-18-2025 21:23 Color:

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 19 जून 2025

सार्थक बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 सम्मेलन के लिए रवाना हुए थे, तो दो मुद्दों पर खासकर सभी की नजर थी - कनाडा के साथ रिश्ते किस तरह आगे बढ़ते हैं और आतंकवाद पर भारत अपना पक्ष किस तरह रखता है। एक ही मंच का इस्तेमाल कर देश ने दोनों को साध लिया। यह आयोजन भारत और कनाडा के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का जरिया तो बना ही, नई दिल्ली ने दुनिया को आतंकवाद के प्रति भी चेता दिया कि इस मामले में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे।

कनाडा से सुधरेंगे रिश्ते

रिश्ते सुधारने का मौका । भारत और कनाडा ने एक-दूसरे के यहां हाई कमिश्नर जल्द से जल्द बहाल करने का ऐलान किया है। यह उस गलती को सुधारने की दिशा में पहला कदम है, जो कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने की थी। राजनयिक संबंध बहाल होने से दूसरे द्विपक्षीय मामलों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिनमें पिछले साल टकराव के बाद से ठहराव आ गया था। इसमें प्रमुख है व्यापार और निवेश समझौता CEPA।

व्यापार बढ़ेगा । एक विस्तृत इकॉनमिक एग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों ने 2010 में बातचीत शुरू की थी। करीब एक दशक तक सब ठीक चला, लेकिन पहले कोरोना की रुकावट आई और फिर कूटनीतिक रिश्ते खराब हो गए। भारत और कनाडा के बीच 2024 में 8.37 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। हालांकि दोनों की इकॉनमी को देखते हुए क्षमता और संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। आर्थिक समझौते से व्यापार आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और अनुमान है कि द्विपक्षीय कारोबार में 6 बिलियन डॉलर तक का इजाफा होगा।

अलगाववाद का मुद्दा । भारत और कनाडा के सामने शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रा, कृषि - तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अपार मौके हैं। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा Top foreign destination रहा है। बातचीत बढ़ने से student visa और वर्क परमिट आसान हो सकता है। पीएम मोदी और मार्क कार्नी की मुलाकात से जो रास्ता खुला है, उसका पूरा फायदा मिले, इसके लिए कनाडा को खालिस्तानी अलगाववादियों से जुड़ी भारत की चिंताओं पर ध्यान देना होगा। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर केस से जुड़े सवाल पर कार्नी का संतुलित जवाब बताता है कि उन्हें भी इस बात का ख्याल है।

आतंकवाद पर अपील । पीएम मोदी ने G7 के outreach session में आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उनका सवाल बिल्कुल ठीक है कि आतंकवाद के प्रायोजक देश और पीड़ितों को एक तराजू में क्यों तौला जा रहा है। जब तक दुनिया के ताकतवर देश आतंकवाद को लेकर अपना नजरिया साफ नहीं करते और अपनी सहूलियत के अनुसार आतंक की परिभाषा तय करने की आदत नहीं छोड़ते, यह समस्या हल नहीं होने वाली।

इन दिनों

गुलमोहर में सोपान

विवेक शुक्ला

1960 के दशक की शुरुआत थी। राजधानी के कुछ पत्रकार अपनी एक कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सरकार से एक प्लॉट की मांग की, सरकार ने देने का वादा किया। उसी दौरान दिल्ली हाउसिंग कमिश्नर के.एल. राठी ने पत्रकारों की प्रस्तावित गुलमोहर पार्क हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों से साहित्यकार डॉ. हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन को भी सोसाइटी का मेंबर बनाने की गुजारिश की। दरअसल, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राठी से कहा था कि वह तेजी बच्चन को पत्रकारों की हाउसिंग सोसायटी में जगह दिलवा दें। इस तरह तेजी बच्चन गैर-पत्रकार होने पर भी हाउसिंग सोसाइटी में शामिल कर ली गईं। नेहरू जी के निधन के दो साल बाद 1966 में सोसाइटी को जमीन मिली, जहां भारत में पत्रकारों की संभवतः पहली आवासीय कॉलोनी गुलमोहर पार्क बनी।

वरिष्ठ लेखक और पत्रकार केदार नाथ गुप्ता की हाल ही प्रकाशित किताब Ink, Saffron and Freedom में गुलमोहर पार्क के बनने की दिलचस्प कहानी बयां की गई है। इसके निर्माण में केदार नाथ गुप्ता का अहम रोल रहा। वह 1960 के दशक में उसकी सोसाइटी के सचिव थे। वह लिखते हैं, 'तेजी बच्चन ने गुलमोहर पार्क कम्युनिटी सेंटर के निर्माण में दिल खोलकर मदद की। उन्होंने अमिताभ बच्चन की 'कुली' फिल्म के प्रीमियर से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी दान किया था।' दरअसल, गुलमोहर पार्क में बच्चन खानदान का पहला घर बना था 'सोपान'। सोपान को बच्चन दंपती ने खड़े होकर बनवाया था। ये सत्तर के दशक के शुरुआती वर्षों की बातें हैं। तब अमिताभ मायानगरी में स्ट्रगलर थे। गुप्ता आगे लिखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन शाम को गुलमोहर पार्क क्लब में मित्रों के साथ बैठकी के लिए जरूर पहुंचते। 'सोपान' की दिवाली सारे गुलमोहर पार्क में मशहूर हुआ करती थी। एक बार दिवाली पर अनार जलाते हुए अमिताभ बच्चन के हाथ जल गए थे। गुलमोहर पार्क के पुराने लोगों को याद है कि हरिवंश राय बच्चन सुनिश्चित करते थे कि अमिताभ की हर फिल्म यहां के उनके मित्र भी देख लें। वह सबको फिल्मों के कैसेट देते थे। कुछ साल पहले बच्चन परिवार ने 'सोपान' को बेच दिया।

एकदा

पड़ोसी का कर्तव्य

गैलीलियो के वैज्ञानिक चमत्कारों से दुनिया भर के लोग प्रभावित थे। उनकी प्रशंसा करने वालों की संख्या कम न थी। लेकिन उनके ही मुहल्ले का एक व्यक्ति उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। वह अक्सर उनसे उलझता और उनकी बुराई करता फिरता था। गैलीलियो यह सब जानते भी उस तरफ ध्यान नहीं देते थे। चूंकि वह तो अपने अध्ययन में लगे रहते। वैसे भी वह शांति हृदय के व्यक्ति थे। एक दिन गैलीलियो को पता चला कि वही पड़ोसी व्यक्ति बहुत परेशान है। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। वह उसे अकेला छोड़कर डॉक्टर को बुलाने भी नहीं जा पा रहा था। कोई उसकी मदद को नहीं आया। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही वह चौंक गया। सामने गैलीलियो एक डॉक्टर के साथ खड़े थे। उन्होंने भीतर आकर मरीज की सेवा की और डॉक्टर से इलाज करवाया। जाते समय उनका पड़ोसी भाव-विह्वल होकर उनके चरणों में झुक गया और बोला, 'मैं तो हमेशा आपका विरोध करता रहा, फिर भी आपने मेरी मदद क्यों की?' गैलीलियो मुस्कराते हुए बोले, 'आपने जो करना चाहा, किया। मैं तो सिर्फ एक पड़ोसी का कर्तव्य निभा रहा था।' यह सुनकर वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया और उसे गैलीलियो से नई सीख मिली।

Subrata Dhar

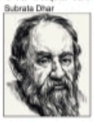

संकलन : दीनदयाल मुरारका

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शुरू हुआ अमेरिकी दबदबे वाला दौर पूरे विश्व के लिए समृद्धि लाया

US कमज़ोर हुआ तो घाटे में रहेगी दुनिया

स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर

इतिहास बताता है कि किसी साम्राज्य के अंत का मतलब है उसके कानूनों और उस पर अमल की प्रवृत्ति का अंत। इसके साथ ही शासन और समृद्धि का भी अंत होता है। अराजकता और लूटपाट का दौर आ जाता है, जब तक कि फिर से कोई नया साम्राज्य न उभर आए।

साम्राज्य बुरा शब्द नहीं । साम्राज्य शब्द के साथ जुड़ी उपनिवेशवाद की स्मृतियों ने आज इसका रूप बिगाड़ दिया है। लेकिन चार्ल्स टिली जैसे इतिहासकार बताते हैं कि नियम आधारित व्यवस्था स्थापित करने, सुरक्षा का माहौल बनाने और समृद्धि का रास्ता साफ करने में ऐतिहासिक तौर पर इसकी बड़ी अहम भूमिका रही है।

खुद अपना दुश्मन । आज हम अमेरिकी आधिपत्य और इससे जुड़े नियमों का अंत होते देख रहे हैं। खास बात है तो यही कि इस बार ऐसा किसी प्रतिद्वंद्वी शक्ति के जरिए नहीं बल्कि खुद अमेरिकी नेतृत्व के हाथों हो रहा है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका की अगुआई में बना अभूतपूर्व समृद्धि का दौर खत्म होने की ओर बढ़ता दिख रहा है।

नफा कम, घाटा ज्यादा । भारत के लिहाज से बहुध्रुवीयता अच्छी चीज रही है। इससे नई दिल्ली के लिए विदेश नीति में लचीलेपन की गुंजाइश बढ़ती है। अफसोस की बात यह है कि भारत इस लचीलेपन से उतना फायदा नहीं उठा पा रहा जितना उसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की दोषपूर्ण मगर उपयोगी विश्वव्यवस्था के नष्ट होने से नुकसान हो रहा है। बेशक अमेरिका ने यह व्यवस्था अपने फायदे की सोच कर बनाई थी लेकिन इससे दुनिया का भी खूब भला हुआ।

अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका । इस पूरे दौर में अमेरिकी प्रभुत्व भले रहा हो, पर उसका रूप औपचारिक अमेरिकी साम्राज्य का नहीं था। पुराने साम्राज्यों के विपरीत अमेरिका ने अपने प्रभाव क्षेत्र यानी कथित 'फ्री वर्ल्ड' को जीत कर उस पर अपना औपचारिक शासन स्थापित नहीं किया बल्कि अपने मित्र देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक, IMF, GATT जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के जरिए नए वैश्विक कानून लागू किए। इससे न केवल GDP बल्कि सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक संस्थानों के अभूतपूर्व विकास का माहौल बना। यह दौर पूर्ण शांति का तो कतई नहीं था। छोटी-मोटी लड़ाइयां, झड़पें चलती रहती थीं, लेकिन बड़ी शक्तियों के टकराव की नौबत कभी नहीं आई।

अमेरिकी दबदबे का अंत

- दुनिया बढ़ रही है बहुध्रुवीयता की ओर
- इस्राइल-ईरान जंग जैसे संघर्ष बढ़ेंगे
- US अपने पैरों पर मार रहा कुल्हाड़ी

सबका साथ, सबका विकास। द्वितीय विश्युद्ध के बाद के इस दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी आधिपत्य बना रहा। इसलिए वह इस स्थिति में रहा कि अपने दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए परोपकार भी करे। उसने कानूनों के जरिए वैश्वीकरण का रास्ता चुना जिससे आर्थिक और नैतिक दोनों मोर्चे सध रहे थे। मजबूत आर्थिक स्थिति की बदौलत अमेरिका ने Gatt और अन्य मंचों पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा रियायतें दीं। उसकी रणनीति अपने हिस्से को बढ़ाकर फायदा कमाने की नहीं बल्कि सबका हिस्सा बढ़ाते हुए लाभान्वित होने की थी।

चौंकाने वाली कामयाबी । इस नीति की कामयाबी किस कदर चौंकाने वाली रही, इसका अंदाजा इतिहासकार एंगस मैडिसन द्वारा किए गए अलग-अलग दौर की प्रति व्यक्ति आमदनी के तुलनात्मक अध्ययन से होता है। उनके मुताबिक ईस्वी सन 1 में प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन में 450 डॉलर, जबकि उत्तर अमेरिका में 400 डॉलर थी। रोमन साम्राज्य के प्रयासों की बदौलत इटली में तब प्रति व्यक्ति आय 809 डॉलर थी। औद्योगिक क्रांति से पहले तक आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रही। लिहाजा, 1700 ईस्वी तक प्रति व्यक्ति आय भारत में 550 डॉलर, चीन में 600 डॉलर, अमेरिका (जो अभी अस्तित्व में नहीं आया था) में 527 डॉलर और पश्चिमी यूरोप में 997 डॉलर थी। लेकिन इसके बाद 1950 से 2003 के बीच यानी मात्र 53 वर्षों में यह भारत में 619 डॉलर से बढ़कर 2160 डॉलर, चीन में 448 डॉलर से 4803 डॉलर और अमेरिका में 9,561 डॉलर से बढ़कर 29,037 डॉलर हो गई।

बदतर होंगे हालात। बहरहाल, कोई भी साम्राज्य रातोरात नष्ट नहीं होता। उसका धीरे-धीरे ही क्षरण होता है। लेकिन तय है कि अमेरिकी अगुआई वाली इस व्यवस्था का नष्ट होना इस दुनिया को बदतर ही बनाएगा। न केवल आपसी संघर्ष बढ़ेंगे और भाईचारा कम होगा बल्कि आर्थिक विकास का चक्का धीमा पड़ेगा।

यहीं नहीं रुकेगी गर्मी

गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश के दर्जनभर से अधिक शहरों में पारा 45 डिग्री के पार हो गया है। रिपोर्ट है कि बारिश भी अनियंत्रित ही होगी। एक नई रिसर्च के मुताबिक बमुश्किल पांच साल में लू वाली गर्मी भरे दिन दोगुने हो जाएंगे। यह कैसे होने जा रहा है, आइए समझते हैं।

इस साल का हाल

- 45° तापमान का रेकॉर्ड टूटा, 3 राज्यों में रेड अलर्ट
- 7 अप्रैल को IMD ने जारी की थी पहली हीटवेव वॉर्निंग
- IMD ने दी थी 10-11 दिन लू की चेतावनी, पर लू के दिन बढ़े
- 57% भारतीय जिले 2025 में अत्यधिक गर्मी के खतरे में
- 2025 बन सकता है इतिहास का सबसे गर्म साल

हिमालय को नुकसान

- हिंदू कुश में इस मॉनसून में दिख सकता है कुदरती कहर
- 72.5% 1980-2024 के बीच बाढ़ का प्रभाव केवल मॉनसून में
- 1980-2024 के बीच बाढ़ का प्रभाव केवल मॉनसून में
- बढ़ेंगी भूस्खलन और ग्लेशियर झीलों के फटने जैसी आपदाएं (ICIMOD)

गर्म दिन दोगुने

IPE ग्लोबल और ESRI की रिसर्च- वेदरिंग द स्टॉर्म

- 2030 तक हीटवेव के दिन दोगुने होने का अनुमान
- 15 गुना बढ़े 1993 से 2024 के बीच में हीटवेव के दिन
- 19 गुना बढ़े 2014 से 2024 के बीच में हीटवेव के दिन

लू ज्यादा होने से बारिश होगी अनियंत्रित

ज्यादा मुसीबत

मुंबई, चेन्नै, दिल्ली, सूरत, ठाणे, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर

- 72% गर्मी का तनाव बढ़ेगा टियर-1 और टियर-2 शहरों में
- 2030 तक तटीय जिले गर्मी से प्रभावित होंगे 69%
- 2040 तक इतने जिले 79%
- जून-सितंबर में समुद्र तटीय गर्मी लंबी चलेगी

बारिश का पैटर्न

इन राज्यों में बढ़ेगी बारिश

80% जिले अनियमित वर्षा का सामना करेंगे इन राज्यों के

एसी की आपदा

गर्मी को बढ़ाने में एयर कंडिशनर का बड़ा रोल

- 2050 तक भारत में करीब 110 करोड़ एसी लगने का अनुमान
- 2020 में देश में करीब 4.8 करोड़ एसी थे
- 2050 तक 99% आबादी को होगी एसी की जरूरत
- 20-28° पर फिक्स किया भारत सरकार ने तापमान (IEA)

बदलती तस्वीर

- 63% हॉटस्पॉट में भूमि-उपयोग बदलेगा 2030 तक
- वन कटने, शहर बनते रहने से और बढ़ेगा पारा
- कटाई और शहरीकरण गर्मी बढ़ाएगा

- साथ ही तूफानी लहरें, बिजली और ओले भी
- जलवायु चरम स्थितियों में अचानक वृद्धि होगी
- अल निनो और ला निना में भी होगी बढ़ोतरी

- शहरीकरण से बने अर्बन हीट आइलैंड
- घरों से हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही
- इमारत में लगें हीट सोखने वाले तत्व
- ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर-वन व तालाब
- एयर कूलिंग की सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बने
- गर्मी के साथ जीने की आदत डालें

- चंद्रभूषण, CEO, iForest

समाधान

- जलवायु-जोखिम वेधशाला की स्थापना जरूरी
- आपदा प्रबंधन समितियों में ताप-जोखिम के लोग रहें
- जोखिम के लिए बने वित्तपोषण का तंत्र

स्रोत : IMD, DTE, AQI
कंटेंट : राहुल पाण्डेय, ग्राफिक : उमेश कुमार

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

प्रकृति की हर आहट में पगा है ईश्वर का संगीत

मयंक मुरारी

हमारे चारों ओर ईश्वर का संगीत व्याप्त है। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, नदियों का कलरव, पक्षियों की चहचहाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और आकाश की गूंज - ये सब उसी संगीत के अलग-अलग स्वरूप हैं। यह केवल वीणा की झंकार या किसी शास्त्रीय वादन तक सीमित नहीं, बल्कि हर तत्व में, हर गति में उसका नाद समाया है।

जब हम बारिश की बूंदों को गिरते सुनते हैं, जब धूप की गरमाहट को महसूस करते हैं, जब ठंडी हवा की कंपकंपी हमारे भीतर तक जाती है - तब भी यह उसी संगीत की एक झलक है। हमारे कदमों की आहट, पंखे की आवाज, बच्चों की खिलखिलाहट - ये सभी उस परमसत्ता की लयबद्ध भाषा के अंश हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, हमारा मन इतना व्याकुल और विचलित है कि हम उस ध्वनि को पहचान नहीं पाते।

जीवन की सरलता ही वह कुंजी है, जिससे हम प्रकृति के स्वर को सुन पाते हैं। जब मन शांत होता है, तभी यह दिव्य संगीत प्रकट होता है। भारत की परंपरा में पशुओं के गले में बंधी घंटियां या घुंघरू सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उनके पीछे एक गहन मनोवैज्ञानिक अर्थ है। ये स्वर पशुओं को संतोष और आनंद देते हैं। कहते हैं कि श्रीकृष्ण की मुरली की धुन सुनकर गाएं रंभाने लगती थीं। गोशालाओं में देखा गया है कि गाय से दूध निकालते समय वहां मधुर संगीत बजा देते हैं।

प्रकृति निरंतर हमें पुकार रही है। पक्षियों के स्वर, गिलहरियों के खेल, फूलों पर मंडराती तितलियों की लय- ये सब हमें आमंत्रण देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। इसका कारण है मन में संवेदनशीलता का अभाव। इसी कारण हम अक्सर थकान या तनाव के क्षणों में संगीत की तलाश में भटकते हैं। शास्त्रीय संगीत में हर भाव के राग हैं और सारे भाव प्रकृति से ही उपजे हैं। जैसे मल्हार राग बारिश के मौसम का अहसास कराता है, तो भैरवी सूर्योदय का। प्रकृति भी हर पल गाती है।

ईश्वर हमारे शरीर के माध्यम से भी संवाद करता है। शरीर की अपनी एक ध्वनि, एक लय है, जिसे हम नहीं समझते। जब जीवन में स्वर नहीं होता, तब नृत्य, उत्सव और आनंद भी नहीं होता। जीवन नीरस हो जाता है। पर जब कोई साधक गहराई से समाधि में जाता है, तब उसे भीतर और बाहर ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। वह अस्तित्व की गूंज है, जिसे विज्ञान भी तरंगों के रूप में मान्यता देता है।

संपूर्ण सृष्टि का स्वभाव उत्सवमय है। सुबह होते ही प्रकृति के सभी अंग मिलकर संगीत रचते हैं। पर्वत, नदियां, वृक्ष, पशु-पक्षी - सब मिलकर ईश्वर की धुन में लीन हो जाते हैं। जीवन की सार्थकता इसी शाश्वत संगीत में खुद को खो देने में है, उसके साथ एक लय में बहने में है। इसलिए जरूरी है कि हम स्वयं को याद करें, अपने भीतर की यात्रा करें और इस दिव्य स्वर के साथ अपने जीवन को संगीतमय बनाएं।

महात्मा से कितने प्रभावित थे आइंस्टाइन

राजीव कुमार वर्मा/जया वर्मा

दक्षिण अफ्रीका में सत्य और अहिंसा के प्रयोग के बाद महात्मा गांधी ने भारत में कई आंदोलनों का सफलतापूर्वक संचालन किया। उनकी दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, इतिहास परखने की क्षमता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया था। उनसे प्रभावित होने वालों में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे।

पहला पत्र । आइंस्टाइन ने 1931 में महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी - आपने दिखाया है कि हिंसा के बिना भी सफल होना संभव है, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने हिंसा का तरीका नहीं छोड़ा है। हम आशा कर सकते हैं कि आपका उदाहरण आपके देश की सीमाओं से परे फैलेगा और एक अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना में मदद करेगा।

बापू का बुलावा । आइंस्टाइन ने पत्र में उम्मीद जताई थी कि किसी दिन वह गांधी से मिल पाएंगे। बापू ने इस पत्र का जवाब 18 अक्टूबर 1931 को दिया। उन्होंने लिखा था, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ी सांत्वना है कि मैं जो काम कर रहा हूं, वह आपकी नजर में अच्छा है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि हम आमने-सामने मिलें और वह भी भारत में मेरे आश्रम में।' सन 1939 में आइंस्टाइन ने लिखा - गांधी की जीवन उपलब्धियां राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय हैं... पूरी सभ्य दुनिया के सचेत रूप से सोचने वाले इंसानों पर उनका नैतिक प्रभाव शायद हमारे समय में क्रूर हिंसक ताकतों के अतिरंजित मूल्यांकन से कहीं ज्यादा स्थायी होगा।

गांधी का प्रभाव । सन 1944 में आइंस्टाइन ने एक बार फिर से महात्मा गांधी को लेकर लिखा - अपने लोगों का एक नेता, किसी बाहरी अधिकार द्वारा समर्थित नहीं, एक राजनेता जिसकी सफलता न तो शिल्पकला पर और न ही तकनीकी उपकरणों की महारत पर निर्भर करती है, बल्कि केवल उसके व्यक्तित्व की दृढ़ शक्ति पर निर्भर करती है - एक विजयी योद्धा जिसने हमेशा बल के प्रयोग का तिरस्कार किया है। ज्ञान और विनम्रता का एक व्यक्ति, जो दृढ़ संकल्प और अडिग स्थिरता से लैस है, जिसने अपनी सारी शक्ति अपने लोगों के उत्थान और उनके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दी है... आने वाली पीढ़ियां, शायद ही कभी इस बात पर विश्वास करेंगी कि इस धरती पर कभी मांस और रक्त से बना ऐसा कोई व्यक्ति चला था।

Subrata Dhar

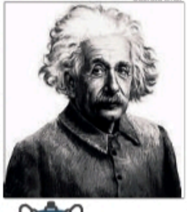

टाइम मशीन

हत्या से दुखी । गांधी की हत्या से आइंस्टाइन को बहुत दुख पहुंचा था। 1948 में उन्होंने इस पर कहा- वह अपने ही सिद्धांत, अहिंसा के सिद्धांत का शिकार होकर मर गए। उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि अपने देश में अव्यवस्था और अशांति के समय उन्होंने व्यक्तिगत सशस्त्र सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया।

अहिंसा की ताकत । आइंस्टाइन ने आगे लिखा था - यह गांधी का अटल विश्वास था कि बल का प्रयोग अपने आप में एक बुराई है, जिसे पूर्ण न्याय के लिए प्रयास करने वालों को त्यागना चाहिए। इस विश्वास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपने दिल व दिमाग में इस विश्वास के साथ उन्होंने एक महान राष्ट्र को उसकी मुक्ति की ओर अग्रसर किया। उन्होंने दिखाया कि लोगों की निष्ठा केवल राजनीतिक धोखाधड़ी और छल के चालाक खेल से नहीं, बल्कि अहिंसा से जीती जा सकती है।

10.81 लाख स्वयं सहायता समूह हैं बिहार में वर्तमान में, जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश में 1.35 करोड़ से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है।

आजकल

कठोर नीति से लगेगी घुसपैठियों पर लगाम

बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में लंबे समय से घुसपैठ जारी है। यह समस्या अब गंभीर रूप धारण कर चुकी है। हालांकि इस दिशा में समाधान किए जाने के उपाय तो बहुत पहले से ही विद्यमान हैं, परंतु उन उपायों पर अब तक ठोस पहल न होने के कारण यह समस्या जस की तस कायम रही। लिहाजा इस संदर्भ में व्यापक स्तर पर नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि घुसपैठियों की पहचान में तेजी लाई जा सके। केंद्र सरकार ने इन घुसपैठियों को समयबद्ध रूप से भारत से बाहर उनके मूल देश भेजने का काम भी तेज कर दिया है

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली

भारत में बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने का अभियान तेज किया जा रहा है। फाइल

बांग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत सरकार की नीति अब तक स्पष्ट और प्रभावी नहीं रही थी। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह स्थिति बदलती नजर आ रही है। इस आतंकी हमले ने एक अप्रत्याशित परिणाम के रूप में सरकार को अवैध प्रवासियों के विरुद्ध संगठित और सख्त नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया है। केंद्र सरकार अब न केवल बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान कर रही है, बल्कि उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है।

इस समस्या के समाधान में बड़ी बाधा यह रही कि बांग्लादेश सरकार घुसपैठ की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। लंबे समय से ढाका यह दावा करता रहा कि उसके नागरिक भारत में अवैध रूप से नहीं जा रहे हैं। पहले एनडीए सरकार के दौरान जब कुछ घुसपैठियों को वापस भेजने की कोशिश की गई, तो वह प्रयास सीमा पर गतिरोध में बदल गया। बांग्लादेश ने उन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इस कारण कोई भी वास्तविक निर्वासन नहीं हो पाया।

भारत में भी राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों ने नीति निर्धारण को और कठिन बना दिया। इस विषय पर दलों की राय उनके राजनीतिक हितों पर आधारित रही। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे मुद्दों पर उठे विवादों ने यह साफ कर दिया था कि घुसपैठ केवल प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है।

राजनयिक मसला : इस बीच भारत-बांग्लादेश संबंधों में 2009 के बाद काफी सुधार हुआ, जब शेख हसीना सत्ता में आईं। हसीना सरकार ने भारत के साथ सुरक्षा और आतंकवाद के मामलों में सहयोग किया। पूर्वोत्तर में सक्रिय कई उग्रवादी समूहों को बांग्लादेश में शरण मिली हुई थी। हसीना सरकार ने उनके कई नेताओं को भारत को सौंप दिया और उनके प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने के निर्देश दिए। व्यापार, ऊर्जा और जल बंटवारे जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में भारत सरकार के लिए, यहां तक कि भाजपा सरकार के लिए भी घुसपैठ के खिलाफ कठोर कदम उठाना राजनयिक रूप से आसान नहीं था।

इस दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो रही थी। राजनीतिक स्थिरता के कारण आर्थिक विकास दर में सुधार हुआ और कुछ समय के लिए बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गई। इस स्थिति में कुछ लोगों ने तर्क देना शुरू किया कि जब बांग्लादेश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो उसके नागरिक भारत क्यों आएंगे। लेकिन यह तर्क आधा-अधूरा था। विकास के बावजूद बांग्लादेश की जनसंख्या पर अत्यधिक दबाव बना हुआ है और संसाधनों की कमी बनी हुई है। आर्थिक विषमता भी एक बड़ा मुद्दा है, जिससे गरीब तबके को कोई लाभ नहीं मिल रहा। यही वर्ग अब भी भारत की ओर अवैध रूप से प्रवास करता है।

रोहिंग्या की समस्या : इस समस्या को और गंभीर बना दिया म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के निष्कासन ने। म्यांमार में अत्याचारों से भागकर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश के काक्स बाजार शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। समय के साथ हजारों रोहिंग्या भारत में भी घुस आए और जम्मू जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बस गए। अनुमान है कि लगभग 40 हजार रोहिंग्या जम्मू में रह रहे हैं। कुछ रोहिंग्या समूहों के चरमपंथ की ओर मुड़ने और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से उनके संबंध सामने आने लगे, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई।

इन तमाम घटनाओं के बाद पहलगाम आतंकी हमला एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हमले की निंदा की, लेकिन सरकार से जुड़े कुछ लोगों के बयान भारत में गहरी चिंता का कारण बने। मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.एल.एम. फजलुर रहमान ने कहा कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए। यद्यपि बांग्लादेश सरकार ने इस बयान से दूरी बना ली, लेकिन इससे पहले अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने चीन में कहा था कि भारत का उत्तर-पूर्व भू-भाग "लैंडलाक्ड" है और केवल बांग्लादेश ही उसका समुद्र मार्ग है। इस प्रकार के बयानों ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को और गहरा किया।

नए नियम : भारत सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को विशेष निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली, असम, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में पहचान और निर्वासन की कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक जो निर्वासन केवल कूटनीतिक चैनलों से होता था और बेहद धीमा होता था, उसमें काफी गति आई है। नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी संदिग्ध प्रवासी के दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। यदि सत्यापन नहीं हो पाता, तो उसे तुरंत निर्वासित कर दिया जाता है। सभी राज्यों को हर महीने की 15 तारीख तक केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है।

दिल्ली में भी विशेष अभियान : दिल्ली में पांच होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां ऐसे लोगों को रखा जा रहा है। पुलिस अब एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) के साथ मिलकर दस्तावेजों और रसद प्रबंधन में काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल अवैध प्रवासियों के खिलाफ, बल्कि उनके नेटवर्क जैसे नकली दस्तावेज बनाने वालों, उन्हें रोजगार देने वालों और मकान किराए पर देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे मामलों में कई एफआइआर भी दर्ज किए हैं।

धरातल पर हो रहा कार्य : सरकार ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है- डाटा साझाकरण और पहचान दस्तावेजों को निष्क्रिय करना। ब्यूरो आफ इमिग्रेशन ने निर्वासित लोगों की सूची सार्वजनिक पोर्टल पर डालनी शुरू कर दी है। यह जानकारी यूआइडीएआइ (आधार), चुनाव आयोग और विदेश मंत्रालय के साथ साझा की जा रही है, ताकि ये लोग दोबारा भारत में घुसपैठ न कर सकें या सरकारी पहचान पत्रों का दुरुपयोग न कर सकें। इस नीति की गंभीरता अब जमीन पर नजर आने लगी है। कुछ अवैध प्रवासी अब स्वयं ही सीमा पर जाकर निर्वासन की मांग कर रहे हैं। वे अपने रिश्तेदारों को वहां बुला रहे हैं कि वे आकर उन्हें वापस ले जाएं।

अब तक भारत की सुरक्षा नीति का मुख्य फोकस सीमा पार आतंकवाद रहा है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश के भीतर घुसपैठ भी एक गंभीर और दीर्घकालिक खतरा है। अब जब सरकार ने स्पष्ट दिशा, समयबद्ध कार्य योजना और अंतर-संस्थागत समन्वय के साथ कदम उठाए हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक मजबूत और प्रभावी नीति वाकई आकार ले रही है। यह नीति न केवल सुरक्षा, बल्कि जनसांख्यिकीय संतुलन और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से भी आवश्यक है।

आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान पर कसे शिकंजा

मनोज वार्ष्णेय

ऐसे समय में जब इजराइल और ईरान में जंग छिड़ी है और दोनों देश अपनी पूरी ताकत से दूसरे देश को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान को समर्थन देने के अतिरिक्त कहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड इजरायल के खिलाफ एकजुट हो जाए। जब दो देशों में जंग हो रही हो और दूसरे देश उसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हों, तब मुस्लिम वर्ल्ड का एकजुट होना, ऐसा कहना क्या पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता नहीं है? क्या वह दुनिया को दो संप्रदाय में बांटकर स्वयं का भला कराने की नहीं सोच रहा है?

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वर्तमान विदेश यात्रा न केवल वैश्विक संबंधों को और मजबूत तथा पारदर्शी बनाएगी, बल्कि इंसानियत का पैगाम भी देगी। अभी रूस-यूक्रेन तथा इजरायल-ईरान एक दूसरे पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, वहीं हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जबरदस्त अशांति है। पाकिस्तान की हालत तो इतनी खराब है कि वहां के नेता जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उन्हें केवल दुत्कार ही मिल रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में जिस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ा, वह भी उसकी कूटनीतिक हार और बेइज्जती का एक हिस्सा माना जा सकता है। पाकिस्तान अभी भी इस बात से सहमा हुआ है कि भारत ने आपरेशन सिंदूर को स्थगित कहा है, न कि समाप्त।

ऐसी स्थिति में वह दूसरे देशों को समर्थन देने की बात करके यह बताना चाहता है कि उसकी स्थिति दूसरों की मदद करने के लिए बेहतर है। जब इजरायल और ईरान में हमला आरंभ हुआ तो भारत ने स्पष्ट तौर पर दोनों से शांति की बात कही, यह भी कहा कि दोनों ही उसके मित्र हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान ने अशांति फैलाने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड एक होने की बात कही। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान पहले भारत के पहलगाम में अपने आतंकवादियों के सहयोग से सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया को पाकिस्तान की मंशा को समझते हुए उस अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। जहां एक ओर भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और शांति-व्यापार-विकास को समर्थन की बात करता है, वहीं पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को ही पोषित करने की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

फिर से

मालदह : आम नहीं, आमों का राजा

जिसने आम खाया हो, पर मालदह न खाया हो, तो उसे यह मान लेना चाहिए कि दरअसल उसने अभी आम खाया ही नहीं है। उसे अभी आम का स्वाद चखना बाकी है। उसे अभी आम का स्वाद सीखना बाकी है। उसे अभी आम के साथ बरतने का हुनर आना बाकी है। उसे अभी प्रेम करना आना बाकी है। जो मालदह का नहीं हुआ, वह किसी का नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के चयन पर सदैव संदेह करना चाहिए, जो आम से प्रेम करें और उसकी पसंद मालदह न हो, ऐसे लोग प्रेम के पात्र ही नहीं। नासमझ हैं।

मालदह संपूर्णता का प्रतीक है। रंग रूप, आकार, व्यवहार सब में। मालदह धातुओं में सोना है। सोना यानी आभूषण में ढाल लो तो सौंदर्य में चार चांद और मुद्रा में ढाल लो अर्थव्यवस्था में वृद्धि। एक भरोसेमंद साथी। मालदह भी ऐसा ही है। एकदम अनूठा। मालदह चमकीला लाल-पीला रंग धारण कर भ्रम नहीं फैलाता। गुलाबखास की तरह लालिमा धारण कर लुभाने का अतिरेक नहीं करता। एक गति के साथ हरे से पीले की ओर बढ़ता है, पर हरा छोड़कर पीला धारण नहीं कर लेता। अपना मौलिक रंग बनाए रखता है। एक सच्चापन है उसमें। इसके स्वाद में भी मौलिकता है। न तो कृत्रिम मीठापन और न ही अधिक रसवाला। न इतने रेशे कि जीभ ही उलझ जाए और न इतना रस कि जूस ही बन जाए। मालदह आम है। आम ऐसा ही होता है जैसा मालदह। आप धरती कहें, पृथ्वी कहें। एक ही बात है।

मालदह अपनी समस्त काया को आम के रूप में एकाकार कर लेता है। ज्यों-ज्यों मालदह अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है, उसका आकार सुघड़ होता जाता है, छिलका बस उतना भर ही अपना अस्तित्व बचाए रखता है कि अंतस पर आवरण चढ़ा रहे, केंद्र में गुठली सिकुड़ कर पुनः बीज रूप धारण करने लग जाती है। संपूर्णता की ऐसी सघन यात्रा है मालदह की। कोई और क्या टिकेगा इसके सामने। पेड़ पर दूर कहीं टिका मालदह यह रूप धरकर जब धरती पर टपकता है तो प्रेम से पूरित पीयूष का आगमन होता है। इस अमृत को छोड़कर किसी और के पीछे कौन भागे भला.....

(सन्नी कुमार की फेसबुक वाल से)

पोस्ट

जिस व्यक्ति की कुंठा और नफरत की वजह से पहलगाम में नृशंस आतंकी हमला हुआ और भारत को आपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, उसी असिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति आवभगत में लगे हैं।
अजय कुमार@AjayKumarJourno

भारत ने कश्मीर को लेकर अपना रुख फिर से स्पष्ट कर दिया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए कोई गुंजाइश नहीं, जबकि पाकिस्तान इसी प्रयास में लगा है। सवाल है कि एक सेना प्रमुख की खुशामद के लिए ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों को कहां तक क्षति पहुंचाने की मंशा रखते हैं।
सीमा सिरोही@seemasirohi

पाकिस्तान के साथ संघर्षविराम और मध्यस्थता को लेकर ट्रंप के बार-बार किए दावों को आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। भारत जब कम समृद्ध था, तब उसने मध्यस्थता का प्रस्ताव नहीं स्वीकारा। अब जब वह कहीं अधिक आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, तब भला कैसे यह स्वीकार कर सकता है।
हुसैन हक्कानी@husainhaqqani

मध्य प्रदेश डायरी

भाजपा में अनुशासन की पाठशाला

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, नईदुनिया, मध्य प्रदेश

पचमढ़ी में 14 से 16 जून तक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए 'संवाद कौशल' की पाठशाला लगाई। अब सवाल उठता है कि जो नेता अपने संवाद कौशल के दम पर ही संसद या विधानसभा तक पहुंचते हैं, उन्हें संवाद कौशल का प्रशिक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल, इसके पीछे की मुख्य वजह अपने विवादित बयान से देशभर में भाजपा की किरकिरी कराने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह हैं। शाह ने अपनी बयानबाजी से कोई सबक लिया हो या नहीं, लेकिन भाजपा ने ही इसे सबक मान लिया। शाह तो कार्रवाई से बच गए और मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को संवाद कौशल प्रशिक्षण देकर यह समझाने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों के विवादित बयानों से मुसीबत में नहीं फंसेगी।

इस शुभारंभ में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अहंकार की मिट्टी हमारे सिद्धांत और उद्देश्यों को धूमिल करती है। जनता जो हमें सम्मान दे रही है, वह हमारा व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि पार्टी का सम्मान है, यह भाव प्रत्येक कार्यकर्ता में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार कार्यकर्ता में यह भाव आ जाता है कि हम तो 30 वर्ष पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या अब भी हमें सीखने की आवश्यकता है, पर हम सीखने की ललक से ही परिवर्तन ला सकते हैं। शाह ने मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों को जो यह बात कही, उसका आशय साफ था कि अहंकार को सिर पर न चढ़ने दो। यह चेतावनी केवल विजय शाह के लिए नहीं थी, बल्कि उन नेताओं के लिए भी है, जो बिना सोचे-समझे उल्टे सीधे बयान देकर भाजपा की उलझन बढ़ाते रहते हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है, जो कहते हैं कि हम तो आठ बार के विधायक हैं, अब आप हमें राजनीति सिखाओगे। ऐसे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि भाजपा अब उन्हें ढोने वाली नहीं है। शाह की बात को समझा जाए तो उन्होंने इशारों में कहा कि जिस पर आप अहंकार कर रहे हो, पार्टी का ये विकास और विस्तार कार्यकर्ताओं की आठ पीढ़ियों के परिश्रम और पुण्य का प्रतिफल है।

पचमढ़ी में भाजपा के विधायकों और सांसदों को संबोधित करते गृह मंत्री अमित शाह। फाइल

दरअसल, संगठन में पीढ़ी परिवर्तन के जारी दौर में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वालों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ती चली गई और चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में भी अधिकतर नए चेहरों को मौका दिया गया। नतीजा यह हुआ कि संगठन में ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता रहा, लेकिन सतह के नीचे समरसता का अभाव बना रहा, जो समय-समय पर सामने भी आया। लंबे समय से पार्टी अनुशासनहीनता के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने से परहेज करती रही है, समझाइश और नोटिस जारी करने से आगे कदम नहीं बढ़ाने का नतीजा हुआ कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भी आपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद विवादित बयान दे दिया, जिसे लेकर पूरे देश में भाजपा की किरकिरी हुई। मोहन सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर असमंजस में रही, इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। लिहाजा मोहन यादव ने अगली कुछ कैबिनेट बैठकों तक विजय शाह को दूर रखा, लेकिन विगत दिनों से वे कैबिनेट में शामिल होने लगे। इसे शाह के लिए संकट के दौर की समाप्ति माना जा सकता है।

तीन दिन के प्रशिक्षण से उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों के विवादित बयानों से मुसीबत में नहीं फंसेगी। प्रशिक्षण वर्ग में सिखाया कि कब-कहां और कितना बोलना है? भाषा कैसी होनी चाहिए? विचारधारा से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समापन सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों-विधायकों को नसीहत दी कि नेताओं को सत्ता के मद में नहीं रहना चाहिए। हम चाहे किसी भी पद पर हों, हमें कार्यकर्ता बनकर ही काम करना चाहिए। जनता से जुड़ाव हो, ईमानदारी से रहो, कर्तव्य का पालन करो, अहंकार पार्टी परिवार और व्यक्तित्व का विनाश करता है। राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने यह समझा दिया कि अहंकार से बचो। यह सीख केवल विजय शाह के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी नेताओं के लिए है, जो बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। पार्टी का संदेश साफ है कि विचारधारा से भाजपा कोई समझौता नहीं करेगी। विजय शाह भले ही अभी कार्रवाई से बच जाएं, लेकिन आने वाले चुनाव में टिकट पाना उनके लिए मुश्किल होगा। यह बात सभी सांसदों-विधायकों और मंत्रियों को समझनी चाहिए।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग का सामना करने के पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए?

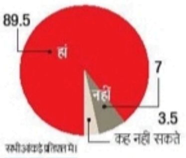

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पीएम मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से दो टूक बात के बाद अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति रवैया कुछ बदलेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

वाइट हाउस में हुआ जब मुनीर का लंच,
समझ लीजिए ट्रम्प का हुआ मामला टंच।
हुआ मामला टंच मदद ले पाकिस्तानी,
ध्वस्त करेंगे ट्रम्प न्यूक्लियर बम ईरानी!
खा कर के दो कौर हुई पोजीशन टाइट,
दिखलाएंगे फिल्म ट्रम्प अब ब्लैक एंड वाइट!!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

सामाजिक बदलाव की धुरी

बिहार में चार माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले दो दशक में वहां बड़ा सामाजिक बदलाव दृष्टिगत हुआ है। देखना यह है कि चुनाव पर इसका कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ेगा

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

देश के राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में आए बिहार को लेकर चर्चा और विमर्श के कई मुहाने एक साथ खुल गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन सबके बीच में इस सूबे का एक नया चरित्र भी उभरा है। यह चरित्र है सामाजिक बदलाव की सीध पर आगे बढ़ते हुए विकास की चुनौतियों पर खरा उतरने का। बिहार जैसा प्रदेश जिसका इतिहास विलक्षण है, उसके इस चारित्रिक उभार के राजनीतिक-सामाजिक तत्वों को समझना दिलचस्प है।

देश में मंडल और कमंडल की राजनीति के अश्वमेध का घोड़ा जब एक साथ दौड़ा तो बिहार की जनता ने राजनीति से जुड़े सामाजिक सरोकारों का तार्किक चुनाव किया। जनता पार्टी के विघटन के करीब एक दशक बाद यह क्षेत्रीय दलों के उभार का दौर था। इस उभार का मस्तूल बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभावी राजनीतिक दलों ने संभाल रखी थी। पर बुरा यह हुआ कि इस उभार के साथ इन दोनों ही प्रदेशों में राजनीतिक अराजकता की एक अपसंस्कृति भी विकसित हुई। अपराध और राजनीति के गठजोड़ के बीच विकसित हुई यह अपसंस्कृति सीधे सत्ता प्रतिष्ठानों तक पहुंची। यहां से संविधान और राजनीति के शुचितापूर्ण साझे को बहाल करने की चुनौती बड़ी थी। बात अकेले बिहार की करें तो बीते दो दशक में राजनीतिक स्थिरता के साथ इस प्रदेश ने विकास और सामाजिक बदलाव की जो राह पकड़ी है, वह अपनी यात्रा में तो लंबी है ही, देश के सामने परिवर्तन, विकास और राजनीति का एक संतुलित माडल भी है।

प्रगतिशील निर्णय : बीते दो दशक में बिहार में आए सामाजिक बदलाव की बात करें तो सबसे पहले 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय का उल्लेख किया जाएगा। देश में ऐसा प्रगतिशील निर्णय लेने वाला बिहार पहला राज्य था। बाद में कई प्रदेशों ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण के सूत्र के साथ महिला सशक्तीकरण का जमीनी आधार तैयार किया। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक पंचायतों में महिला नेतृत्व ने अपने निर्णयों और कार्यशैली से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती दी है। यह भी कि ये सारे वे राज्य हैं, जहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति और लैंगिक गैरबराबरी को लेकर चिंता सबसे ज्यादा व्यक्त की जाती रही। वर्ष 2006 में ही बिहार सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया। इसी तरह, 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला। आगे चलकर 2013 में बिहार पुलिस में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इन फैसलों से प्रदेश में महिलाओं के बीच बहाल हुए आत्मविश्वास का नतीजा है कि बिहार में आज 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह हैं। इससे प्रदेश में 1.35 करोड़ महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की महिलाओं की साक्षरता दर में 20 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज हुई। इस कारण बिहार को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। महिला साक्षरता दर का सीधा प्रभाव महिला प्रजनन दर पर पड़ा, जो 4.3 से घटकर 2.9 पर पहुंच गई।

आज सुशासन को लेकर खूब बात होती है। पर इस बात को लेकर यह विवेक हर स्तर पर नदारद दिखता है कि इसके लिए सामाजिक आचरण और व्यवहार में शुचिता को लेकर सबसे पहले पहल करनी होगी। गौरतलब है कि देश में सुशासन बाबू की छवि गढ़ने में सफल रहे नीतीश कुमार ने इस दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की। यह साल था 2016, जब राजनीतिक नफा-नुकसान की परवाह किए बगैर बिहार में सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तीकरण के लिहाज से एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने शराबबंदी लागू कराया। आज बिहार में शराबबंदी के नौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। कई तरह की स्खलनों की शिकार मौजूदा राजनीतिक संस्कृति में इस तरह के निर्णय का नैतिक साहस दिखाना बड़ी बात है। यह बात तब ज्यादा समझ में आती है जब हम देखते हैं कि कुछ माह पूर्व एक प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को शराब घोटाले में जेल तक की हवा खानी पड़ी।

आज बिहार में सुशासन के बूते सामाजिक बदलाव का एक बड़ा आधार तो तैयार हुआ ही है, इसने राजनीतिक पंडितों की उस क्यासबाजी की भी हवा निकाल दी है, जिसमें देश में बड़े राजनीतिक बदलाव के बीच यह कहा जाने लगा था कि विकास के चमकदार कंगूरों के बीच देश में समाजवादी मूल्यों की राजनीति का दौर बीत गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में सामाजिक आधार पर बदलाव की यह धुरी कितनी निर्णायक साबित होती है।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा बिहार। फाइल

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 19 जून 2025

दैनिक जागरण

वार-वार दोहराए जाने से भी असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता

मोदी की ट्रंप से खरी बात

प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन में इन देशों की आतंकवाद पर दोहरी नीति को उनके सम्मुख ही बेनकाब करने के साथ वहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर लंबी वार्ता में जो कुछ कहा, उससे अमेरिका को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि भारत कश्मीर अथवा अन्य किसी मामले में किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यह अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक था कि भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप के इन दावों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहते कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर संघर्षविराम कराया और इसके लिए दोनों देशों से व्यापार करने का प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं था और भारत से इस संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुई। इसका अर्थ है कि ट्रंप का बार-बार दोहराया जाने वाला दावा फर्जी है। पता नहीं क्यों मोदी की खरी बात के बाद भी वे इस पर अड़े हैं? मोदी ने दो टूक शब्दों में यह भी साफ किया कि भारत ने कश्मीर पर न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की है और न ही करेगा। ट्रंप को यह सच सुनना अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब भारत आर्थिक रूप से इतना सशक्त और आज जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर कद भी नहीं रखता था, तब यदि उसने कश्मीर पर किसी को बीच-बचाव करने का मौका नहीं दिया तो फिर आज ऐसा कैसे कर सकता है? यदि ट्रंप और उनके सहयोगी यह साधारण सी बात नहीं समझते तो इसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते।

आज इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि अमेरिका का वह प्रभाव नहीं रहा, जो दो-तीन दशक पहले हुआ करता था। यह भी कटु सत्य है कि ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की फजीहत ही अधिक हो रही है। बड़ी-बड़ी बातें करने के बावजूद ट्रंप न तो रूस-यूक्रेन युद्ध रोक सके और न ही अपनी मनमानी टैरिफ नीति पर कायम रह सके। यह सही है कि वे अपने ढंग के अनोखे राष्ट्रपति हैं और कई बार राजनयिक शिष्टाचार भी भुला देते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि भारत उनके अनुचित दबाव में आ जाए। भारतीय प्रधानमंत्री ने एक जरूरी काम यह भी किया कि उन्होंने कनाडा से अमेरिका आ जाने के ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य था, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान के जिहादी सोच और आतंक को खुला समर्थन देने वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। यदि ट्रंप को अपने निजी स्वार्थों के चलते पाकिस्तान की हरकतें स्वीकार हैं तो वे उन्हें मुबारक। यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को युद्ध के रूप में ही देखेगा। यह पाकिस्तान को भी सीधा संदेश है।

सख्ती का संदेश

हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग उन स्कूलों के अध्यापकों, मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को दंडित करेगा, जिनके यहां परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम रहा है। इसके साथ शिक्षा बोर्ड का कामकाज सुधारने पर भी चर्चा हुई है। यह स्वागतयोग्य है कि शिक्षा विभाग के नीति नियंता हर पक्ष को गंभीरता से ले रहे हैं। यह वास्तव में चिंता का विषय होना चाहिए कि ऐसे स्कूल भी हैं, जहां परिणाम 25 प्रतिशत भी नहीं रह पाया। आशा करनी चाहिए कि दायित्व निश्चित होंगे और दायित्व बोध जगेगा, लेकिन इसके साथ ही यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि ऐसा परिणाम आने के कारण क्या हैं। क्या नकल करने का मौका नहीं मिला या पढ़ाई का स्तर ही ऐसा था? शिक्षा बोर्ड के पास शायद ही हर स्कूल के परीक्षा संचालन की सीसीटीवी फुटेज हो। स्कूल निजी हों या सरकारी, परीक्षा संचालन में एकरूपता अनिवार्य है। अच्छी प्रतियोगिता वही होती है, जिसके मानक सबके लिए समान होते हैं। धावकों को एक जैसा धरातल भी मिले। उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वालों पर भी निगरानी रखी जाए और परीक्षा संचालन से जुड़े व्यक्तियों पर भी। पाठशालाओं का निरीक्षण नियमित किया जाए और जवाबदेही तय जाए तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल किसी से पीछे रहेंगे। विश्वास करना चाहिए कि सरकार के पास यह जानकारी तो होगी ही कि उच्च विद्यालयों में प्रवेश का स्रोत यानी पांचवीं तक के स्कूलों में स्थिति क्या है। यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र के सुधार अनवरत जारी रहें।

> शिक्षकों पर कार्रवाई के साथ यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि खराब परिणाम के कारण क्या रहे

आत्मचिंतन की मांग करता उत्तराखंड

अशोक कुमार

तमाम दबावों के चलते हेलीकाप्टर सेवा संचालन में आवश्यक एसओपी के उल्लंघन ने केदारनाथ के लिए इस सेवा को असुरक्षित बना दिया है

केदारनाथ यात्रा भारत की पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक है। इसकी जड़ें सैकड़ों वर्षों पुरानी हैं और आदिगुरु शंकराचार्य के समय तक जाती हैं। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा और तप से भरी आध्यात्मिक यात्रा है। पिछले दस वर्षों में इस यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। 2013 की भीषण बाढ़ और उसके बाद हुए पुनर्निर्माण एवं प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 1990 के प्रारंभ में जहां प्रतिदिन औसतन केवल 2,500 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे, वहीं आज यह संख्या 30,000 से अधिक हो चुकी है। प्रतिवर्ष 20 लाख से भी अधिक यात्री हर सीजन में केदारनाथ यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की केदारनाथ जी में आस्था जहां सुखद अनुभूति है, वहीं व्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से एक चुनौती भी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ संवेदनशील हिमालयी वातावरण और पहाड़ों की भारवाहक क्षमता पर दबाव डाल रही है। जब विषय आस्था और भावना से जुड़ा हो, तब भीड़ रोकने के नियमों का पालन कराना कठिन हो जाता है। दुर्भाग्यवश अब यह यात्रा कुछ लोगों के लिए 'स्टेटस सिंबल' बन गई है।

2013 की त्रासदी के बाद भूगर्भीय बदलावों से पैदल मार्ग को 14 किमी से बढ़ाकर 19 किमी करना पड़ा। अब यह मार्ग और कठिन हो गया है, विशेषकर बुजुर्गों के लिए। अब पैदल मार्ग पर घोड़े भी चलते हैं, जो यात्रा को असुरक्षित बना रहे हैं। राहत के रूप में शुरू की गई हेलीकाप्टर सेवा भी आज सुविधा के साथ एक चुनौती बन गई है। ये उड़ानें ध्वनि प्रदूषण करती हैं, जीवाश्म ईंधन जलाती हैं और पर्वतीय जलवायु को क्षति पहुंचाती हैं। हेलीकाप्टर से लोग अल्प समय में गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, जहां तापमान, हवा का दबाव और आक्सीजन भी कम होती है। इससे व्यक्ति खुद को मौसम के अनुकूल नहीं ढाल पाता, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं।

उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथारिटी हेलीकाप्टर सेवा का संचालन करती है। यात्रियों के टिकट का मूल्य 7,000 से भी कम रखा है। क्योंकि इतने में तो कभी-कभी घोड़े भी नहीं मिलते। इससे हेलीकाप्टर टिकट प्राप्त करना एक चुनौती बन गया है। लंबी कतारें, टिकटों की कालाबाजारी, फर्जी वेबसाइटों के जाल में फंसना आम है। जब मौसम साफ रहे, तब भी अधिकतम 2,000 यात्री ही प्रतिदिन हेलीकाप्टर से यात्रा कर सकते हैं, पर टिकटों की मांग 10,000 से भी अधिक होती है। इससे वीआइपी सिफारिशों का प्रशासन पर दबाव बना रहता है। इस क्षेत्र में मौसम अत्यंत अनिश्चित होता है। कभी-कभी तो कुछ ही मिनटों में दृश्यता शून्य तक पहुंच सकती है, जिससे सुरक्षित लैंडिंग कठिन हो जाती है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर उड़ान भरने का दबाव पायलटों और प्रशासन पर बना रहता है। अगर मानक संचालन प्रक्रियाओं(एसओपी) को सख्ती से लागू किया जाए, तो दुर्घटनाओं की आशंका घट सकती है, पर इससे उड़ानों की संख्या घटेगी, जो व्यावसायिक रूप से हेलीकाप्टर संचालकों के लिए अनुकूल नहीं। श्रद्धालुओं में भी असंतोष बढ़ता है और वे खराब मौसम में भी हेलीकाप्टर संचालन की मांग करते हैं। इन कारणों से हेलीकाप्टर आवश्यकता से अधिक चक्कर लगाते हैं, जिससे उनके रखरखाव की उपेक्षा होती है और तकनीशियनों पर सीमित समय में उनकी सर्विसिंग का दबाव होता है, ताकि अधिक उड़ानों की अव्यावहारिक मांग पूरी की जा सके। खराब मौसम, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और समय के दबाव में कभी-कभी तकनीकी त्रुटि हो जाती है, जो जानलेवा साबित होती है। इसी 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट और एक बच्चे सहित सात तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई। खराब मौसम और दृश्यता की कमी इस दुर्घटना के मुख्य कारण रहे। पायलट ने निर्धारित समय से पहले उड़ान भरी और प्रतिकूल मौसम के बावजूद उड़ान जारी रखी। यह इस वर्ष की चारधाम यात्रा की पांचवीं हेलीकाप्टर दुर्घटना थी।

अवधेश राजपूत

हेलीकाप्टर आपरेटरों, वीआइपी यात्रियों और तीर्थयात्रियों के दबाव के चलते हेलीकाप्टर सेवा संचालन में आवश्यक एसओपी के उल्लंघन ने इस सेवा को असुरक्षित बना दिया है। यह स्थिति गहन आत्मचिंतन की मांग करती है। सुरक्षित और टिकाऊ यात्रा के लिए बहुआयामी उपायों की आवश्यकता है। सबसे आवश्यक है एक उच्च गुणवत्ता और बड़ी क्षमता वाला रोपवे सिस्टम, जैसा स्विट्जरलैंड में है। यह घोड़ों और हेलीकाप्टर यात्रा, दोनों का एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। यह पर्यावरण हितैषी भी होगा। इसके अस्तित्व में आने पर घोड़ा संचालकों के लिए समुचित पुनर्वास योजना बनाई जानी चाहिए। मौसम-आधारित उड़ान प्रतिबंध अनिवार्य किए जाने चाहिए। सभी हेलीपैड्स पर रीयल-टाइम मौसम निगरानी प्रणाली होनी चाहिए। पायलटों को पर्वतीय उड़ान का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए और उनके ड्यूटी घंटे नियंत्रित किए जाएं। हेलीपैड्स को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाए और केवल दोहरे-इंजन, उच्च रखरखाव वाले हेलीकाप्टरों को ही अनुमति दी जानी चाहिए। सभी हेली सेवाओं के लिए एटीसी की तरह एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ एसओपी तथा सुरक्षा सलाह को व्यापक रूप से प्रचारित एवं लागू किया जाने की भी आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ देश के अन्य पर्वतीय स्थलों में भी किया जाना चाहिए और विशेष रूप से वहां, जहां हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इस हादसे से हमें चेत जाना चाहिए।

केदारनाथ मात्र एक गंतव्य स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। भीड़भाड़, वाहनों के अत्यधिक दबाव और व्यावसायीकरण ने इस पवित्र धाम के आत्मा को खतरे में डाल दिया है। असुरक्षित हवाई यात्रा, पर्यावरणीय क्षरण और अव्यवस्था से उपजी चिंताएं प्रशासन, श्रद्धालुओं, हेली सेवा प्रदाताओं और समाज, सभी से गहन एवं ईमानदार आत्मविश्लेषण की मांग करती हैं।

(लेखक उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं)

response@jagran.com

सैन्य कार्रवाई पर सस्ती राजनीति

सुरेंद्रकिशोर

विपक्षी दल इस गलतफहमी में हैं कि उनकी बयानबाजी से लोग सैन्य कार्रवाई के लिए पीएम मोदी को श्रेय नहीं देंगे

वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत का श्रेय आंध्र के एक कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा की उपाधि देकर दिया था, पर आज आपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय विपक्षी दल खासकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को देने से कतरा रही है। कांग्रेस का यह रवैया पुराना है। 2019 में पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर तब कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने कहा था, 'इसके लिए मैं वायुसेना के पायलटों को सलाम करता हूं।' क्या ऐसा कुछ है कि 1971 में युद्ध शुरू करने का आदेश तो प्रधानमंत्री देती थीं, पर 2019 में और अब ऐसे फैसले सेना स्वतः लेने लगी है? चूंकि जनता सब जानती है, इसलिए लगता नहीं कि कांग्रेस के कहे का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। 2019 में कांग्रेस नेतृत्व यह दर्शाना चाहता था कि एयर स्ट्राइक का निर्णय वायुसेना ने खुद लिया, जबकि यह जगजाहिर है कि सेना चुनी हुई सरकार के अधीन कार्य करती है। वह खुद से सीमा पार कार्रवाई नहीं करती। इसके लिए उसे सरकार आदेश देती है। इस पर हैरानी नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 2014 की अपेक्षा अधिक सीटें मिलीं।

सामरिक महत्व के मामलों पर कैसी सस्ती राजनीति होती है, इसका परिचय बीते दिनों दिनों बंगाल विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से संबंधित प्रस्ताव से भी मिला। उसमें सैन्य कार्रवाई के लिए सेना की प्रशंसा करते हुए उसे धन्यवाद दिया गया, पर उसमें आपरेशन सिंदूर का उल्लेख नहीं किया गया। बांग्लादेश युद्ध में विजय के बाद इंदिरा गांधी ने उसका चुनावी लाभ किस तरह उठाया था, इसके प्रमाण मीडिया रिपोर्ट में दर्ज हैं। 1972 के प्रारंभ में कुछ विधानसभाओं के चुनाव होने वाले थे। तब चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह बात छिपाने की कोशिश नहीं की कि 'भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत इंदिरा गांधी के सफल नेतृत्व का प्रतीक है और उनका हाथ मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस की ही सरकार होनी चाहिए। मजबूत केंद्र सरकार होने के कारण ही विदेशी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सका। अब गरीबी खत्म करने के लिए केंद्र और राज्यों का तालमेल होना आवश्यक है।' (दिनमान-5 मार्च, 1972)। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने मतदाताओं के नाम एक चिट्ठी भी कई भाषाओं में जारी की। उसे चुनावी राज्यों में घर-घर पहुंचाया गया। उसमें इस पर जोर दिया गया था कि 'देशवासियों की एकता और उच्च आदर्शों के प्रति इंदिरा जी की निष्ठा ने हमें युद्ध जिताया। अब उसी लगन से हमें गरीबी हटानी है। इसके लिए प्रदेशों में हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है, जिनका केंद्र से बढ़िया तालमेल हो।'

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के साथ राहुल गांधी। फाइल

चूंकि 1974 तक 1971 की जीत का यश जनता के दिल और दिमाग में नहीं रहता, इसलिए इंदिरा ने बिहार और उत्तर प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव दो साल पहले ही करवा दिए थे। इन दोनों राज्यों में चुनाव 1974 में तय थे। हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने इंदिरा के रुख के विपरीत सार्वजनिक रूप से कहा था, 'चुनाव आवश्यक प्रतीत नहीं होता।' पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने भी समय पूर्व चुनाव का विरोध किया, पर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के प्रादेशिक नेतृत्व की एक न सुनी। ऐसा ही उन्होंने बिहार में भी किया, जहां भोला पासवान शास्त्री की सरकार चल रही थी।

इसमें दोराय नहीं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने सही समय पर साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इस कारण आमजन की भावना उनके साथ थी। यदि उन्होंने चुनावी लाभ लेने के लिए अतिरिक्त प्रयास न किया होता तो भी उन्हें उसका लाभ मिलता, पर लगता है उन्हें धैर्य नहीं था। आपरेशन सिंदूर के बाद देश की आम भावना सेना के साथ-साथ मोदी सरकार के पक्ष में है। किसी भावी चुनाव में उसका लाभ भाजपा-राजग को मिलने की संभावना है, पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल ऐसी ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे उनकी साख खराब हो रही है। उनके इस रवैये से देश के बाहर यह संदेश भी जा रहा कि ऐसे नाजुक मौके पर भारत में एकता नहीं है। प्रतिपक्ष को यह गलतफहमी है कि उसकी बयानबाजी से आम लोग मोदी को श्रेय देना बंद कर देंगे।

चुनावी इतिहास बताता है कि जब भी भारतीय सेना विजयी होती है, उसका चुनावी लाभ सत्ताधारी दल को मिलता है और हारने पर खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। उपचुनावों पर भी उसका असर पड़ता है। 1962 में चीन के हाथों पराजय के बाद 1963 में लोकसभा की चार सीटों के लिए उपचुनाव हुए। उनमें जेबी कृपलानी, डा.राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और मीनू मसानी गैर-कांग्रेस दलों के प्रत्याशी थे। दीनदयाल उपाध्याय को छोड़कर तीनों विजयी रहे, जबकि प्रधानमंत्री नेहरू और कांग्रेस ने इन नेताओं को हराने की बड़ी कोशिश की। प्रतिपक्ष की यह जीत चीन के हाथों पराजय का नतीजा थी, पर 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया तो कांग्रेस 1967 के लोकसभा चुनाव में जीत कर फिर केंद्र की सत्ता में आ गई। इसीलिए विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस के लिए अच्छा यही होगा कि वह ओछी राजनीति करना बंद करे और आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी दिखे।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहिंसा की शक्ति

हिंसकवृत्ति व्यक्ति को कसाई बना देती है। ऐसे लोग जब तक किसी के साथ हिंसक व्यवहार न करें, तब तक उन्हें बेचैनी सी रहती है। इतिहास में ऐसे कुछ विकृत दिमाग के लोग हुए हैं, जिन्हें यातना देकर किसी को मारने में आनंद आता था।

हिंसा के माहौल में अहिंसा के दीपक भी यत्र-तत्र प्रज्वलित होते ही हैं। भले ही अहिंसा एवं शांति की लौ धीमी हो, लेकिन यह हिंसा एवं अशांति से कहीं बेहतर एवं कारगर है। जिनकी जीवनशैली हिंसाप्रधान होती है, उनकी दृष्टि में हिंसा ही हर समस्या का समाधान होता है। हिंसा एक मिथ्यादर्शन, किंतु हिंसकवृत्ति के लोगों ने उसे सम्यक दर्शन बना दिया है। जो जितनी बड़ी हिंसा करता है, उसे उतना ही सफल माना जाने लगा है। बड़े राष्ट्र इसी तरह की हिंसा के बल पर दुनिया पर अपना आधिपत्य करते हैं। बात शांति की हो, अहिंसा की हो और मार्ग हिंसा एवं अशांति का चुने तो यह कैसे संभव हो सकता है? गुलाबों की बरसात कभी नहीं होती। अगर आपको ज्यादा गुलाब चाहिए तो आपको गुलाब के ज्यादा पौधे लगाने के लिए मेहनत करनी होगी। ऐसा ही अहिंसा एवं शांति को चाहने वालों को भी करना होगा।

भारत की जीवनशैली अहिंसाप्रधान रही है, जो मानती है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध जीते गए, किंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान हुआ तो शांति एवं अहिंसा द्वारा। जब जीवनशैली अहिंसाप्रधान बनती है तो आदमी शांति का अनुभव करता है, जबकि हिंसाप्रधान जीवनशैली तनाव, भय और आशंका बढ़ाती है। माफिया नींद बहुत कम ले पाते हैं। कड़ी सुरक्षा में भी वे असुरक्षित महसूस करते हैं। भय से तनाव और तनाव से अशांति कैसे पैदा होती है, यह उनके जीवन में साफ-साफ देखा जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा भी है कि अहिंसा ही धर्म है, वही जीवन का एकमात्र रास्ता है।

देवेंद्र ब्रह्मचारी

विश्व पर मंडराता कृषि आतंकवाद का खतरा

योगेश कुमार गोयल

चीन के दो नागरिकों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में एक खतरनाक फफूंद को अवैध रूप से पहुंचाने की कोशिश की

फसलें केवल भोजन का स्रोत नहीं होतीं, बल्कि वे किसी देश की आर्थिक रीढ़, सामाजिक स्थिरता और वैश्विक प्रभुत्व का भी आधार होती हैं। इन्हीं फसलों पर जब कोई जैविक हमला होता है तो यह केवल कृषि संकट नहीं रह जाता, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का गंभीर मुद्दा बन जाता है। हालिया घटनाएं इस ओर संकेत कर रही हैं कि अब आतंकवाद का रूप बदल रहा है। बंदूकों और बमों की जगह अब बीज, कीटाणु और फफूंद हथियार बन रहे हैं, जिन्हें 'एग्रो-टेररिज्म' यानी 'कृषि आतंकवाद' कहा जा रहा है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में सामने आए एक मामले ने तो समूचे वैश्विक जैविक सुरक्षा तंत्र को ही झकझोर कर रख दिया है। चीनी मूल के दो नागरिकों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में एक अत्यंत खतरनाक फफूंद 'फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम' को अवैध रूप से शोध के बहाने पहुंचाने की कोशिश की। यह फफूंद न केवल फसल नष्ट कर सकती है, बल्कि इसके कारण उत्पादित अनाज मनुष्यों और पशुओं के लिए जहरीले हो सकते हैं।

'फ्यूजेरियम ग्रेमिनीअरम' नामक फफूंद गेहूं, मक्का, चावल और जौ जैसी प्रमुख फसलों को 'हेड ब्लाइट' और 'सीडलिंग राट' जैसी बीमारियों से संक्रमित करती है। संक्रमित फसलों के कारण उल्टी, दस्त, यकृत और प्रजनन संबंधी विकारों की आशंका रहती है। यह फफूंद मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को भी अस्थिर कर सकती है। यह खतरा भारत के लिए कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि यहां की लगभग 54 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे जैविक खतरे की दृष्टि से अधिक संवेदनशील बनाती है। भारत की जैविक अनुसंधान प्रयोगशालाएं अभी इस खतरे की निगरानी, पहचान और पूर्व चेतावनी प्रणाली से लैस नहीं हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चिंताजनक है। भारत में जैविक तस्करी के जोखिम को देखते हुए खाद्य एवं कृषि मंत्रालय को उच्च स्तरीय बायोसेफ्टी टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए, जो विज्ञानियों, सैन्य अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का समावेश कर एक मजबूत नीति बना सके।

वैज्ञानिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब उसी स्वतंत्रता का उपयोग जैविक हथियारों की तस्करी और आतंकी प्रयोग के लिए किया जाए, तब विज्ञानियों को जवाबदेही के दायरे में लाना अपरिहार्य हो जाता है। जब कोई तंत्र फफूंद या विषाणु के जरिए फसलों को संक्रमित करता है तो वह धीरे-धीरे पूरे विश्व की खाद्य श्रृंखला को जहरीला बना देता है। यह पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक घातक है। विश्व में हर राष्ट्र को अपने जैविक संसाधनों, फसलों और बीजों की सुरक्षा को रक्षा नीति का हिस्सा बनाना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

जनभागीदारी से आर्थिक उन्नति संभव

'आर्थिक रूप से और सक्षम बनने का समय' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जीएन वाजपेयी ने संदेश दिया है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय अनुशासन, डिजिटल निवेश और आर्थिक जागरूकता को अपनाना होगा, ताकि राष्ट्र की समग्र प्रगति सुनिश्चित हो सके। आर्थिक मुद्दे केवल आंकड़ों की चमक से नहीं, बल्कि आमजन की भागीदारी से ही चमकेंगे। नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त होने की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। भारत को विकसित बनाने की दौड़ अब सिर्फ नीति-निर्माताओं की नहीं, नागरिकों की समझदारी की भी कसौटी है। बीते वर्षों में हमने आर्थिक नीतियों में निरंतर सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और डिजिटल पेमेंट क्रांति देखी है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? यदि आम व्यक्ति अभी भी पारंपरिक बैंकिंग सोच से चिपका रहेगा, तो आर्थिक समावेशन अधूरा रहेगा। यहां विचार का मूल संदेश यह है: वित्तीय ज्ञान अब वैकल्पिक नहीं, आवश्यक है। एसआइपी, म्यूचुअल फंड, डिजिटल निवेश प्लेटफार्म-इनकी पहुंच जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही जरूरत है भरोसे, समझ और अनुशासन की। केवल बचत नहीं, बल्कि रणनीतिक निवेश और दीर्घकालीन सोच ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की कुंजी है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यह बात केवल शहरी भारत तक सीमित न रह जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वित्तीय जागरूकता को शिक्षा की तरह स्थान मिलना चाहिए। अगर देश के हर नागरिक को निवेशक की मानसिकता मिल जाए, तो 'डेमोग्राफिक डिविडेंड' असली शक्ति में बदल सकता है। यह विश्लेषण यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या हम केवल विकास देखना चाहते हैं या खुद उसके भागीदार भी बनना चाहते हैं?

awanishg30@gmail.com

विमान यात्रियों की सुरक्षा पर संकट

संपादकीय आलेख 'विमान यात्रियों का संकट' बेहद संवेदनशील और विचारणीय है। बीते दिनों दो बेहद ही मार्मिक विमान हादसों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जब देश आधुनिकता के हर क्षेत्र में धीरे-धीरे बुलंदी को छू रहा हो, ऐसे में जरा सी तकनीकी खामी के कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये लगातार हो रहे हादसे हमारी तकनीकी कुशलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। एक तरफ अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मृतकों की ठीक तरीके से शव पहचान भी नहीं हो सकी, इसी दरमियान उत्तराखंड में हुई एक और हेलीकाप्टर दुर्घटना में भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज के समय में हवाई यात्रा निःसंदेह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। जब ''हवाई चप्पल पहनने वाले'' लोगों को ''हवाई जहाज की यात्रा'' करवाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा हो, तब इन हादसों ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। यह अनिवार्य है कि सरकार और एयरलाइंस मिलकर हवाई यात्रा की सुरक्षा और तकनीकी निगरानी को प्राथमिकता दें, ताकि आम नागरिकों की जान की कीमत किसी भी चूक की भेंट न चढ़े।

आयुष कुमार, मोकामा, पटना

क्यों हिंसक बन रहे हैं बच्चे?

हाल में आस्ट्रिया के गाज शहर में एक प्रसिद्ध स्कूल में ऐसी ही एक घटना घटी। सुबह के समय जब स्कूल में हलचल चल रही थी, तभी स्कूल का एक पूर्व छात्र हाथ में बंदूक लेकर वहां आया। वह वहां मौजूद छात्रों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर बाद में खुद को भी गोली मारकर ली। इस घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक शिक्षिका भी शामिल है। विकसित देशों में 'गन कल्चर', माता-पिता से बच्चों को मिला हिंसक व्यवहार का संस्कार, परिवार में कलह, माता-पिता का बच्चों पर ध्यान न देना और 'स्पेस' देने के नाम पर खुद ही मस्त रहने जैसी कई वजहें इन घटनाओं के पीछे होती हैं। बच्चों में मानसिक विकार और डिप्रेशन होना तथा उस पर समय पर इलाज न होना भी एक बड़ा कारण है। दुनिया का सबसे समृद्ध और विकसित देश अमेरिका इस तरह की घटनाओं में पहले नंबर पर है। वहां हर कुछ दिनों में स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिलती हैं।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मैल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सैक्टर-63, नोएडा
ई-मैल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सैक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****